● वर्ष-6

● अंक-01

रायपुर, रविवार
09 अगस्त 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6>> क्या है हिंदू देवियों का रहस्य...

महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी : रिजिजू

नई दिल्ली। देश में महिलाओं को राजनीति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक घमासान का केंद्र बन गया है। महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन और परिसीमन विधेयक को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस छिड़ गई है।

विवाद की शुरुआत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उस टिप्पणी के बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वहां की महिलाएं अपनी बात मुखर होकर नहीं कहेंगी।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चुटकी लेते हुए इसे कांग्रेस के हृदय परिवर्तन की संज्ञा दी और विधेयक को बिना शर्त समर्थन देने की उम्मीद जताई। कानून लागू करने में देरी और परिसीमन पर विवाद रिजीजू के बयान का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया (एक्स) पर सवाल उठाया कि 2023 में सर्वसम्मति से पारित हो चुके %महिला आरक्षण विधेयक% को तीन साल बाद भी लागू क्यों नहीं किया गया है?

उन्होंने सरकार पर इसे बेवजह परिसीमन से जोड़ने का आरोप लगाते हुए बिना किसी शर्त के कानून लागू करने की मांग की। इसके जवाब में रिजीजू ने संवैधानिक बारीकियों का हवाला देते हुए कहा कि 2023 का संविधान संशोधन जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ा है।

उन्होंने तर्क दिया कि नई जनगणना और जातिगत आंकड़ों के प्रकाशन में समय लग सकता है, जिससे आरक्षण 2034 के चुनावों तक टल सकता है। अत: 2029 के आम चुनावों में इसे लागू करने के लिए जल्द परिसीमन आवश्यक है। हालांकि, कांग्रेस ने सरकार पर 2011 के पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कराने के लिए महिला आरक्षण को %ढाल% बनाने का आरोप लगाया।

कर्नाटक कैबिनेट में महिला प्रतिनिधित्व पर तीखे बाण

कर्नाटक कैबिनेट में महिला प्रतिनिधित्व पर तीखे बाण इस बहस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो गए। रिजिजू ने निशाना साधते हुए याद दिलाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के प्रभाव वाले मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं है, जो कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाता है।इस पर शिवकुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि महिला आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करने वाली कांग्रेस ही थी और भाजपा को उनकी पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

भाजपा के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने जहां कांग्रेस पर प्रतिनिधित्व के मार्ग में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए महिला आरक्षण को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। दोनों पक्षों के इस कड़े रुख से आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने के संकेत मिल रहे हैं।

न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के लिए बनेगा राष्ट्रीय आयोग, अगले सप्ताह लोकसभा में आएगा विधेयक

नई दिल्ली। विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए एक आयोग गठित करने वाला विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया जा रहा है। प्रस्तावित न्यायाधिकरण सुधार विधेयक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति तथा उनकी योग्यता में दक्षता बढ़ाना, स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, पारदर्शिता लाना और एकरूपता कायम करना है।

अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किए जाने वाले इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यालय वाले प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य होंगे।प्रस्तावित आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश पात्र होंगे। लोकसभा सदस्यों को वितरित किए गए विधेयक में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था।शीर्ष अदालत ने इन प्रावधानों को शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत माना था। अदालत ने यह भी कहा था कि ये प्रावधान न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और कामकाज से जुड़े मानकों को स्पष्ट करने वाले पहले के न्यायिक फैसलों के अनुरूप नहीं हैं।सुप्रीम कोर्ट ने दिया था राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था, जो स्वतंत्र हो और जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो। अदालत ने कहा था कि आयोग को विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन एवं नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनानी चाहिए।विधेयक के कानून बनने के बाद न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 समाप्त हो जाएगा।

प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के छात्रों को दिया विकसित भारत का विजन

बोले- जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है

नईदिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह आज आपके परिवार वाले गर्व महसूस कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सभी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि कई छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल मिले हैं। मैं आप सभी को दिल से बधाई देता हूँ। हालाँकि, अगर उनमें कुछ और लड़कियाँ भी होतीं तो और भी अच्छा होता। माफ़ कीजिए। सिर्फ़ एक या दो ही क्यों? और भी होनी चाहिए थीं।

इसके साथ ही मोदी ने कहा कि आज आईआईटी दिल्ली में एआई से जुड़े कुछ नए पहल भी शुरू हुए हैं। मैं इसके

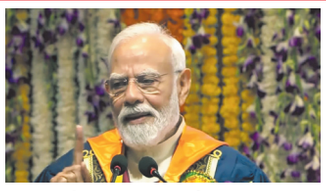

लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि आज आप सभी और सारे छात्रों इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। हर छात्र के मन में आने वाले कल की अपनी-अपनी तस्वीर होगी। कई छात्र अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी में होगा, कई साथी अपने नए स्टार्टअप का सपना देख रहे होंगे, किसी ने अगले प्रतियोगी परीक्षा का लक्ष्य बनाया होगा। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सपना अलग है। लेकिन इन सबके बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक सा होगा।मोदी ने कहा कि वो दिन याद करिए जब आपका आईआईटी दिल्ली में पहला दिन था और एक आज का दिन है। आप सोच रहे होंगे कि अभी कल की ही तो बात है, जब अभिविन्यास हुआ था और अब ये दीक्षांत समारोह का समय भी आ गया। Orientation से Convocation की इस यात्रा का आपको भरपूर satisfaction भी होगा। और साथ ही आप सभी में जीवन के एक नए चेप्टर की शुरुआत का उत्साह भी होगा।

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा: मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज शाम यहां राजधानी रायपुर के महोबा बाजार स्थित एक निजी होटल में आयोजित आईटीवी नेटवर्क और इंडिया न्यूज के युवा मंच कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अब छत्तीसगढ़ समन्वित रूप से प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक पूरे प्रदेश के लक्ष्यकेंद्रित विकास के लिए सरकार संकल्पित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्टजनों सम्मानित किया।

युवा मंच कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद एक बड़ी बाधा थी। हमारी सरकार के गठन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद विषय पर हुई बैठक में यह तथ्य हमारे सामने आया कि देश में शेष नक्सल समस्या का अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में ही था। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति से एक डेडलाइन तय हुई और हमारे सुरक्षाबल के जवानों ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त बना दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की अपार संभावना है। बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध है। धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल किया है। वहाँ बम्बू राफ्टिंग जैसी पर्यटन गतिविधियां संचालित हैं और होम स्टे में पर्यटक आकर रुक रहे हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई उद्योग नीति में पर्यटन को भी शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में धर्मांतरण रोकने सबसे सख्त कानून लाने वाला प्रदेश है। प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर अब कड़ी कार्यवाही की जा रही है। अन्य प्रदेशों के कानूनों का विस्तार से अध्ययन करके छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएससी में भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। प्रदेश में अब पीएससी से लेकर सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हो रही हैं और युवाओं के साथ उनके अभिभावक भी अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर निश्चिंत हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार युवाओं से लगातार संवाद कर रही है। उनके सभी सुझावों का स्वागत है। युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं। विकास की नीति निर्माण में युवाओं के सुझाव महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है।

प्रमुख समाचार

सुखबीर सिंह बादल के बाद पीएम मोदी से मिले राघव चड्ढा

नई दिल्ली। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और चुनाव वाले राज्य पंजाब में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। आपको बता दें कि पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। भाजपा

सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यह सुबह मेरे लिए यादगार रहेगी। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का सौभाग्य मिला। हमारी बातचीत विस्तृत और ज्ञानवर्धक रही। अपना कीमती समय देने और उनसे मिली सीख व मार्गदर्शन के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। 7 अगस्त को शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। यह बैठक शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पीएम मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद हुई। राघव ने इस मुलाकात को यादगार सुबह बताया।राघव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का सौभाग्य मिला।

गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है सपा : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) के ब्राह्मण प्रेम पर तीखा प्रहार करते हुए शनिवार को कहा कि सपा अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए गिरगिट की तरह रंग

बदलती रहती है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बसपा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली सर्वसमाज-हितैषी आंबेडकरवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में हमारी चार बार की सरकार भी इसी आधार पर चली है, जबकि सपा अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए जगजाहिर तौर पर गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। उन्होंने सपा के पीडीए फॉर्मूले पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा, सपा द्वारा प्रचारित पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में पहले पी से पिछड़ा बताया जाता था। लेकिन अब ब्राह्मण समाज को बसपा से तेजी से जुड़ता देख सपा ने पी का मतलब पंडित कर दिया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा शिविर का दौरा किया

नईदिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के दिलशाद गार्डन इलाके में दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के निकट स्थित एक कांवड़ शिविर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। गुप्ता ने एक सभा

को संबोधित करते हुए कहा, ''चाहे वित्तीय सहायता हो, सफाई व्यवस्था हो या बिजली-पानी की आपूर्ति, दिल्ली सरकार ने सुनिश्चित किया कि कांवड़ शिविरों का रखरखाव बेहतर ढंग से हो। पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे भोले के भक्तों को किसी भी तरह की समस्या भी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया गया है।'' दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा 2026 के लिए कांवड़ समितियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी थी। मंत्रिमंडल के फैसले के तहत 20 हजार वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैले और छह से बारह दिन तक आयोजित होने वाले कांवड़ शिविरों के लिए अब वित्तीय सहायता 15 लाख रुपये कर दी गई है।

अमेरिकी बिल को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली। भारत समेत कई देशों पर 100 फीसदी टैरिफ का प्रावधान करने वाले अमेरिकी विधेयक पर विपक्षी दलों ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश और आर्थिक नीतिक की नाकामी करार दिया। इसके अलावा, विपक्षी पार्टी के नेता पवन खेड़ा और आम आदमी पार्टी (आप)

के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं इसे मोदी सरकार की विदेश और आर्थिक नीति की नाकामी मानता हूं। हम कई वर्षों से रूस से सस्ते दाम पर ईंधन खरीद रहे हैं। भारत कितना और किससे ईंधन खरीदे, यह फैसला भारत को करना चाहिए, अमेरिका को नहीं। अमेरिका हम पर दबाव नहीं बना सका। अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंध वाले विधेयक को मंजूरी मिलने पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, क्या आपको लगता है कि भारत सच में स्वतंत्र है? जो भी आता है, भारत को धमकाता है। जो भी आता है, अपनी शर्तें थोपता है।

यूपी भाजपा ने क्षेत्रीय व मोर्चा प्रभारियों की सूची जारी की

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश ने संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए क्षेत्र एवं मोर्चा प्रभारियों की घोषणा की है। पार्टी की सूची के अनुसार छह नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामप्रताप सिंह चौहान को पश्चिम, गीता शाक्य को ब्रज, शंकर लोधी को कानपुर

और दिलीप पटेल को अवध क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। वहीं रमेश सिंह को काशी तथा अभिजात मिश्रा को गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। मोर्चा स्तर पर भी पार्टी ने प्रभारियों की नियुक्ति की है। राजेश चौधरी को युवा मोर्चा और संजय राय को पिछड़ा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। डॉ. धर्मेंद्र सिंह को अनुसूचित मोर्चा, कामेश्वर सिंह को महिला मोर्चा तथा डॉ. प्रियंका रावत को अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देवेश कोरी को अल्पसंख्यक मोर्चा और शंकर गिरी को किसान मोर्चा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गोविंद नारायण शुक्ला को मुख्यालय प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश मंत्री नरेंद्र शर्मा को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर को विस्तारक योजना , अर्चना मिश्रा को 'मन की बात' संयोजक और राहुल वाल्मीकि को सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।

आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीक

सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं और विकसित भारत की मजबूत नींव

जगत प्रकाश नड्डा

भारत ने पिछले एक दशक में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार किया है। सरकारी और निजी क्षेत्र में अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जांच केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। यह सरकार की ऐसी नीतियों को दर्शाता है, जिनका केंद्र आम नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए काम किया है। इन लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है कि देश में लोगों द्वारा अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी कमी आई है। यह खर्च पहले 65 प्रतिशत तक था, जो अब घटकर 43 प्रतिशत रह गया है। जिला अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात शिशु से लेकर बड़े अस्पताल में इलाज करा रहे कैंसर मरीज तक, आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में भरोसेमंद, अच्छी गुणवत्ता वाले और किफायती चिकित्सा उपकरण बेहद जरूरी हो गए हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसके लिए प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाने, गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने, बीमारियों की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और आपात स्थिति से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर निवेश किया जा रहा है। जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अब जोर एक आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीक क्षेत्र तैयार करने पर है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को और सस्ता, आसानी से उपलब्ध और किसी भी संकट के समय मजबूत बनाना है।

पहले ,भारत कई आधुनिक और जटिल चिकित्सा उपकरणों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों से होने वाले आयात पर निर्भर था। इन तकनीकों से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तो हुआ, लेकिन इससे इलाज की लागत बढ़ी, आपूर्ति व्यवस्था पर बाहरी निर्भरता बनी रही और इन उपकरणों की पहुंच सीमित रही। इसी जरूरत को देखते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 में देश के भीतर आधुनिक चिकित्सा उपकरण बनाने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया

गया। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों को सस्ता बनाना ैर जांच की लागत कम करना है। सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के पूरे क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, चिकित्सा उपकरण पार्क और दवा एवं चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजना शामिल हैं। इन पहलों से देश में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण, नए शोध, निवेश और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर माहौल तैयार हो रहा है। नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 50 से अधिक आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का देश में उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है, जो वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि भारत धीरे-धीरे दुनिया के चिकित्सा तकनीक क्षेत्र में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में उभर रहा है। सिर्फ चिकित्सा उपकरणों का निर्माण केंद्र बनने के अलावा, भारत तेजी से आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अपना भी रहा है, ताकि लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सके। आधुनिक जांच सुविधाओं, शरीर की अंदरूनी तस्वीर लेने वाली मशीनों, शरीर में लगाए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों, गहन चिकित्सा की मशीनों और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती दर पर उपलब्ध कराने से मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होता है। साथ ही इलाज की गुणवत्ता और समय पर इलाज मिलने में भी सुधार होता है। देश में ही चिकित्सा उपकरण बनने से विदेशों से आयात पर निर्भरता घटती है, आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होती है और लागत कम करने के अवसर बढ़ते हैं।

भारत का विश्व स्तर पर पहचान बना चुका दवा उद्योग, मजबूत इंजीनियरिंग क्षमता, तेजी से फैलता डिजिटल ढांचा, तेजी से बढ़ता नए उद्यमों का क्षेत्र और कुशल मानव संसाधन अगली पीढ़ी की चिकित्सा तकनीक विकसित करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चिकित्सा उपकरण के रूप में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर (एसएमडी) , इंटरनेट से जुड़े चिकित्सा उपकरण, रोबोट आधारित तकनीक और दूर से जांच जैसी नई तकनीकों में भारत के पास देश और दुनिया की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए नए समाधान विकसित करने के बड़े अवसर हैं। जैसे-जैसे भारतीय कंपनियां दुनिया के बाजार में विस्तार कर रही हैं, गुणवत्ता भी भारत में बने चिकित्सा उपकरणों की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है। सरकार नियामक व्यवस्था को मजबूत करने, मान्यता प्राप्त जांच सुविधाओं का विस्तार करने, चिकित्सा उपकरणों की प्रभावशीलता से जुड़े वैज्ञानिक प्रमाण तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था विकसित करने पर जोर दे रही है।

बारिश के बाद कीचड़ में तब्दील हुई सड़क, लगी वाहनों की कतार

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मध्यप्रदेश के जबलपुर से अमरकंटक, केंवची होते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को रतनपुर और बिलासपुर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-45 बारिश के दौरान राहगीरों के लिए मुसीबत बन चुका है। निर्माणाधीन सड़क की बदहाल स्थिति और बारिश के बाद जगह-जगह बने कीचड़ के कारण इस मार्ग पर आए दिन जाम लग रहा है। शनिवार को एक बार फिर एनएच-45 पर जाम लग गया। बताया जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर यह तीसरी बार है, जब इस मार्ग पर यातायात बाधित हुआ है।

जानकारी के अनुसार, केंदा से दारसागर, मझवानी और बासाझाल के बीच सड़क की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है।सड़क निर्माण के दौरान ठेका कंपनी ने सड़क के निचले हिस्सों और खराब जगहों पर मिट्टी डालकर फिलिंग की थी।लेकिन बारिश के बाद ये मिट्टी कीचड़ में बदल गई। कीचड़ में भारी मालवाहक वाहनों के पहिए धंसने लगे, जिसके कारण छोटे वाहन कीचड़ में फंस गए।देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहन की कतारें लग गई।

कीचड़ में यात्री बस, कार, ट्रक और अन्य छोटे-बड़े वाहनों के फंसने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।कई वाहन चालक घंटों तक जाम खुलने का इंतजार करते रहे।मार्ग पर यातायात प्रभावित होने से यात्रियों का समय बर्बाद हुआ। जरुरी काम से आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएच-45 मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है।

इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री और मालवाहक वाहन गुजरते हैं। इसके बावजूद निर्माणाधीन हिस्से में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा रही है।बारिश के दौरान सड़क की स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे वाहन फंसने और जाम लगने की समस्या लगातार बढ़ रही है।

लगातार जाम की स्थिति से लोगों में ठेका कंपनी और संबंधित विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।स्थानीय लोगों ने सड़क के खराब हिस्सों को तत्काल दुरुस्त करने, कीचड़ वाले स्थानों पर उचित मटेरियल डालने तथा यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है, ताकि महत्वपूर्ण एनएच-45 पर बार-बार लगने वाले जाम से राहगीरों को राहत मिल सके।

पामेड़ की छात्राओं ने कलेक्टर से मांगा हॉस्टल

20 किमी पैदल चलकर स्कूल जाने को मजबूर बेटियां

बीजापुर। छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा से लगे पामेड़ क्षेत्र की दो दर्जन से ज्यादा स्कूली छात्राएं शुक्रवार को टैक्सी से बीजापुर पहुंचीं। छात्राओं ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने पामेड़ में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए स्थायी छात्रावास की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल नहीं होने के कारण उन्हें दूरदराज के गांवों से रोज कठिन परिस्थितियों में स्कूल पहुंचना पड़ता है। छात्राओं ने बताया कि पामेड़ में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर की छात्राओं के लिए वर्तमान में कोई स्थायी छात्रावास उपलब्ध नहीं है।कवरगट्टा, धर्माराम, जीडपल्ली, सपेड़, मीनागट्टा, उड़तमल्ला और रासपल्ली सहित आसपास के गांवों की छात्राओं को रोज करीब 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है।

छात्राओं का कहना है कि पक्की सड़क की सुविधा नहीं है। कच्चे और दुर्गम रास्ते से स्कूल आते हैं। दूरी भी ज्यादा है और रास्ता भी खराब है। बहुत परेशानी होती है। कई बार समय पर स्कूल भी नहीं पहुंच पाते और घर लौटने में भी देर होती है। छात्राओं ने बताया कि उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। कई अभिभावक सुरक्षा और आने जाने की समस्या के कारण अपनी बेटियों की पढ़ाई छुड़ाने को मजबूर हो रहे । कुछ छात्राएं पहले ही स्कूल छोड़ चुकी हैं। छात्राओं के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमलेश कारम भी जिला शिक्षा अधिकारी से मिले। उन्होंने छात्राओं की समस्या को गंभीर बताते हुए स्थायी समाधान की मांग की। पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमलेश कारम ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र की बेटियों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्थायी हॉस्टल बनने तक छात्राओं के लिए शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी राजेश पांडे ने बताया कि छात्राओं का आवेदन मिला है।

शादी के 3 दिन बाद अचानक गायब हुई दुल्हन, अब कर रही पैसे की मांग

सरगुजा। जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश निवासी रामकली बाई ने पुलिस अधीक्षक सरगुजा को लिखित शिकायत सौंपकर मामले में कार्रवाई और न्याय की मांग की है। शिकायत में शादी के बाद दुल्हन के अचानक घर से चले जाने और दूल्हे पक्ष से दोबारा पैसों की मांग किए जाने का आरोप लगाया गया है।

पीड़िता के मुताबिक, उनके बेटे तुलसीदास लोधी की शादी 23 मई 2026 को जमगला निवासी एक युवती के साथ हुई थी। शिकायत के अनुसार, विवाह कराने में जमगला निवासी दो मध्यस्थों की भूमिका थी।

रामकली बाई का आरोप है कि शादी के दौरान दूल्हे पक्ष से 1 लाख रुपये नकद और करीब 1 लाख रुपये के जेवर लिए गए थे। शादी के बाद दुल्हन करीब तीन दिन तक ससुराल में रही।

आरोप है कि चौथे दिन रात में दुल्हन शौचालय जाने की बात कहकर घर से बाहर निकली और फिर वापस नहीं लौटी। परिजनों का दावा है कि कुछ लोग उसे चुपचाप अपने साथ ले गए।

शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि जब ससुराल पक्ष दुल्हन को वापस लाने के लिए पहुंचा तो उनसे कथित तौर पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग की गई। पीड़ित पक्ष ने इसे सुनियोजित तरीके से की गई ठगी बताते हुए आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

पीड़ित पक्ष के अनुसार, मामले को लेकर 6 अगस्त 2026 को लखनपुर थाने में आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने, दिए गए पैसे और जेवर वापस दिलाने की मांग की गई।

जर्जर सड़क के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा

धरना प्रदर्शन कर किया आंदोलन

कोरबा। छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में बदहाल सड़क को लेकर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बालको एरिया की सड़के काफी जर्जर है। इन सड़कों की खराब हालत और कथित उदासीनता के खिलाफ वकीलों ने शुक्रवार को कड़ा रुख अपनाया। लंबे समय से बदहाल सड़कों के कारण आम जनता को परेशानी हो रही है। इसके अलावा राहगीरों और वाहन चालकों को भी दिक्कतें हो रही है। इसे लेकर कोरबा के अधिवक्ताओं ने बालको प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बाद बालको प्रबंधन की तरफ से वकीलों को आश्वासन मिला। जिसके बाद वकीलों ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद आंदोलन समाप्त किया। वकीलों ने बालको प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के भीतर सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्य नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

स्थानीय लोगों और वकीलों का कहना है कि बालको क्षेत्र की मुख्य सड़कें और मेजर ध्यानचंद चौक दर्री-बालको मार्ग पूरी तरह से जर्जर है। भारी वाहनों के निरंतर आवागमन, कोयला और राखड़ परिवहन के कारण सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। यहां बारिश होने पर कीचड़ और बारिश थमते धूल के गुबार और गड्ढों के कारण लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। प्रशासनिक बैठकों और शिकायतों के बावजूद सड़क मरम्मत की दिशा में ठोस कदम न उठाए जाने से अधिवक्ताओं में काफी गुस्सा है।अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर बालको प्रबंधन और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गणेश कुलदीप का कहना है कि औद्योगिक विकास के नाम पर क्षेत्र की जनता को केवल प्रदूषण, जर्जर सड़कें और बीमारियां मिल रही हैं। जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मार्ग से हमारे अधिवक्ता संघ के लगभग डेढ़ सौ वकील रोज आवागमन करते हैं। कपड़े मैले हो जाते हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं। इसलिए आज हम न्यायालय में प्रैक्टिस छोड़कर सड़क पर उतर आए हैं। जिससे मुद्दे की गंभीरता को समझा जा सकता है। यदि जल्द से जल्द सड़कों का डामरीकरण या मजबूतीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू नहीं किया गया, तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगामरम्मत शुरू करेंगे = बालको प्रबंधन की ओर से मौके पर मौजूद प्रखर सिंह ने कहा कि इस मार्ग के लिए बालको का जो अंश था, वह जिला प्रशासन को प्रदान कर दिया गया है। सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाना है। निर्माण जल्दी शुरू होगा। जिस सड़क के लिए अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को आंदोलन किया। लंबे समय से इस सड़क की मरम्मत जरूरी है। इसका उपयोग मुख्य तौर पर बालको प्लांट द्वारा ही किया जाता है।

जर्जर भवन, टपकती छत और शौचालय तक नहीं

9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं बदहाल भवन में पढ़ने को मजबूर हैं. बारिश के मौसम में एमसीबी में बड़ा हादसा हो सकता है

एमसीबी। कछौड़ में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है. यहां स्कूल भवन जर्जर है. बारिश के दिनों में हालात और भी बदतर हो गए हैं. छत से पानी टपकने के कारण कई कक्षाओं में पानी भर जाता है. बच्चों की कॉपी-किताबें और ड्रेस तक भीग जाती हैं.

बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा भी नहीं है. उन्हें शौच के लिए स्कूल परिसर से बाहर जाना पड़ता है. शिक्षकों ने बताया कि छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में ज्यादा है. यहां स्कूल भवन, शौचालय, बिजली, खेल मैदान और प्रयोगशाला जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याएं हैं.

शिक्षिका ने बताया कि प्रयोगशाला का एक कमरा भी बेहद जर्जर स्थिति में है और गिरने की कगार पर है. विधायक के दौरे के दौरान भी विद्यालय की समस्याओं से संबंधित मांग और शिकायतें लिखित रूप से दी गई थीं. शिक्षक लगातार हर साल अपनी समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन अबतक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है.

मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने अब स्कूल की स्थिति का निरीक्षण करने की बात कही है. एमसीबी जिला शिक्षा अधिकारी रविकांत यादव ने कहा कि उन्हें स्कूल की समस्याओं की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है. बीईओ के साथ विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और मौके पर वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे.

जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि निरीक्षण के बाद ही स्कूल की वास्तविक स्थिति और अन्य समस्याओं के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि निरीक्षण के बाद आवश्यक व्यवस्था करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी.

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

छोटे भाई के झगड़े का बदला लेने गांव पहुंचे युवक गिरफ्तार

सूरजपुर। सूरजपुर के महंगई स्थित स्कूल में छोटे भाई के साथ हुए लड़ाई का बदला लेने आरोपी अपने साथी के साथ हथियार लेकर पहुंचा। युवकों की गतिविधि संदिग्ध होने पर नवापारा गांव में ही लोगों ने घेर लिया और पुलिस को सूचना दी। कार की तलाशी लेने पर धारदार चाकू और नकली बंदूक बरामद किया गया है। पूरा मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, महंगई स्थित स्कूल में कक्षा 11वीं के दो छात्रों के मामूली विवाद हुआ। एक छात्र ने घर पहुंचकर पूरी घटना बताई, जिसके बाद गुस्से में बड़ा भाई अपने साथी के साथ नवापारा गांव पहुंच गया। जहां ग्रामीणों को जब कार सवार युवकों की गतिविधि पर शक हुआ तो उन्होंने गाड़ी को घेरकर पुलिस को सूचना दी। चाकू और नकली बंदूक मिलने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नकली बंदूक असल में लाइटर था और उसे डराने के लिए रखा गया था, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

स्वतंत्रता दिवस पर जिले में होगा उल्लास महा-चौपाल का आयोजन

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। कलेक्टर विजय दयाराम केके मार्गदर्शन में उल्लास-नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जिले में उल्लास महा-चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने बताया कि उल्लास कार्यक्रम का मूल मंत्र जन-जन साक्षर और कर्तव्य बोध है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वयस्कों को सशक्त बनाना है, जो स्कूली शिक्षा से वंचित रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साक्षरता को देशभक्ति से जोड़ते हुए जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में उल्लास महा-चौपाल एवं विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 14 अगस्त की पूर्व संध्या पर समुदाय की सहभागिता से उल्लास साक्षरता मोबाइल टॉर्च रैली, मशाल रैली एवं प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के पश्चात उल्लास शपथ, महा-चौपाल, कहानियों का कारवां, मातृत्व साक्षरता, अंगूठा मुक्त पंचायत, डिजिटल साक्षरता एवं सेल्फी प्वाइंट, अंगूठे से कलम तक सम्मान समारोह का आयोजन होगा।

जिले में 9 से 17 अगस्त तक होंगे विविध आयोजन

जीपीएम। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम का आयोजन 9 से 17 अगस्त तक किया जाएगा। साथ ही 14 अगस्त को 'भारत विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस' के अवसर पर जिले में विभिन्न स्मृति एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर ने कार्यक्रमों के प्रभावी एवं व्यवस्थित आयोजन के लिए डिप्टी कलेक्टर विक्रांत अंचल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं जिला शिक्षा अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर भारत विभाजन के दौरान प्रभावित लोगों के संघर्ष, पीड़ा एवं बलिदान को स्मरण करते हुए जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को शासन के निर्देशानुसार दोनों कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए जनभागीदारी के साथ गरिमापूर्ण एवं प्रभावी आयोजन करने के निर्देश दिए हैं।

नशे का जाल नाबालिगों से नशीली गोलियां बरामद

दुर्ग। मेडिकल नशे का नेटवर्क दुर्ग जिले में लगातार फैलता नजर आ रहा है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के आईटीआई मैदान के पास पुलिस ने दो नाबालिगों को संदिग्ध हालत में पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 600 नशीली गोलियां बरामद हुईं। दोनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस सप्लाई चेन और मुख्य हैंडलर की तलाश कर रही है। इसी बीच हाल ही में चंद्रशेखर आजाद स्कूल का मामला भी सामने आया था, जहां आठ छात्रों ने एक साथ नशीली गोलियां खा ली थीं। जांच में पता चला कि एक छात्र के भाई, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, घर पर नींद की गोलियां लेकर आए थे। छात्र उन्हीं गोलियों को स्कूल ले गया और अपने साथियों में बांट दिया। पुलिस ने इस मामले में भी नियम के मुताबिक कार्रवाई की है। एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि अब पुलिस मेडिकल नशे के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए एंड-टू-एंड जांच कर रही है। संवेदनशील इलाकों में विशेष पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। लगातार थाना क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है।

शादी से इनकार पर आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल

बिलासपुर। तखतपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवक ने शादी के लिए युवती को प्रपोज किया।लेकिन जब युवती ने शादी से इनकार किया तो युवक ने आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल कर दिया। युवती की शिकायत पर तखतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। तखतपुर थाना प्रभारी अवनीश कुमार पासवान ने बताया कि एक युवती की इंस्टाग्राम के जरिए बलौदाबाजार जिले के रहने वाले युवक से दोस्ती हुई थी। फिर दोनों के बीच व्हाट्सएप पर भी बातचीत होने लगी। इसी दौरान युवक ने युवती के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर रख लिया। बाद में युवती को इस बात का पता चला। युवती ने शादी से इनकार कर दिया। आरोपी ने कथित तौर पर उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। घटना से परेशान युवती ने मामले की शिकायत तखतपुर थाना में दर्ज कराई।

दंतेवाड़ा में सेवा सेतु से आसान हुआ सरकारी दस्तावेज बनवाना

दंतेवाड़ा। बस्तर के दूरदराज और अंदरूनी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए सरकारी दस्तावेज बनवाना अब पहले के मुकाबले आसान हो गया है। आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए अब लोगों को बार-बार तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। जिला प्रशासन की पहल से सेवा सेतु पोर्टल और सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके गांव या आसपास ही कई सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

सेवा सेतु अभियान का उद्देश्य आम लोगों तक सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समय पर

पहुंचाना है। इसके तहत आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विवाह पंजीयन और नाम सुधार जैसी कई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस सुविधा से ग्रामीणों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो गई है।

दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचना कई बार काफी मुश्किल होता है। आने-जाने में पैसा खर्च होने के साथ पूरा दिन भी लग जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले एक दस्तावेज बनवाने के लिए कई बार कार्यालय जाना पड़ता था। अब सेवा सेतु केंद्रों में कर्मचारी आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में मदद करते हैं। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बच रहा है।

इसी सुविधा का लाभ बड़े बचेली के कोआपारा निवासी राजू कुंजाम ने भी लिया। उन्होंने अपने बेटे रेवांथ कुंजाम के निवास प्रमाण पत्र के लिए सेवा सेतु केंद्र में आवेदन किया। राजू कुंजाम ने बताया कि उनके बेटे की आगे की पढ़ाई और शैक्षणिक कार्यों के लिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी था।

दंतेवाड़ा तहसीलदार पीएन बंजारे ने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल ग्रामीणों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों के नजदीक पहुंचाना है, ताकि दूर-दराज के लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए मुख्यालय न आना पड़े।

उन्होंने बताया कि सेवा सेतु केंद्र के अलावा लोग मोबाइल फोन के जरिए भी पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

बस्तर में मक्का खरीदी के नाम पर 34 किसानों से 24 लाख की ठगी

जगदलपुर। बस्तर जिले से किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ मक्का खरीदी के नाम पर 34 भोले-भाले किसानों से करीब 24 लाख रुपये की ठगी की गई है। हालांकि, शिकायत मिलने के तुरंत बाद मुस्तैद हुई बस्तर पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बस्तर के एडिशनल एसपी (स्क) सुखनंदन राठौर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह पूरा घटनाक्रम भानपुरी थाना क्षेत्र का है। इलाके के चेराकूर, कुंगारपाल और खड़गा गांव के किसानों ने अपनी सालभर की मेहनत से उगाई मक्के की फसल को बेचने के लिए एक स्थानीय

खरीदार से सौदा किया था।आरोपी ने किसानों से भारी मात्रा में मक्का खरीद लिया। पैसे तुरंत देने के बजाय उसने किसानों को एक कागजी रसीद थमा दी और वादा किया कि जल्द से जल्द उनके बैंक खातों में या नगद पैसा पहुंचा देगा। लेकिन जब भुगतान का समय आया, तो आरोपी ने चालाकी दिखाई। उसने पहले तो किसानों के फोन उठाना बंद कर दिया और फिर अचानक अपने घर से फरार हो गया।

काफी दिनों तक पैसा नहीं मिलने और खरीदार का कोई अता-पता न होने पर परेशान किसानों ने भानपुरी थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब गंभीरता से जांच शुरू की, तो 24 लाख रुपये की इस बड़ी ठगी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस टीम ने तुरंत जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान सहदेव मंडावी के रूप में हुई है, जो पड़ोसी जिले कोंडागांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (ब्नहस) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन में शामिल हुए वित्त मंत्री

रायपुर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन एवं ग्रामोद्योग विभाग की स्वदेशी प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की समृद्ध हथकरघा परंपरा, बुनकरों और शिल्पकारों के योगदान को रेखांकित करते हुए उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की हथकरघा कला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय हुनर की पहचान है। बुनकरों के कौशल को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और आर्थिक अवसरों से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि और स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर आयोजित स्वदेशी प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक हथकरघा एवं ग्रामोद्योग उत्पादों ने प्रदेश की कला, संस्कृति और शिल्प कौशल की विविधता को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में स्थानीय बुनकरों एवं शिल्पकारों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया।

रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 स्थित मंदिर में ओपी चौधरी ने की भगवान शिव की पूजा

रायगढ़। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने शनिवार को रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना करते हुए प्रदेश में जनकल्याण, सुख-शांति एवं सर्वसमृद्धि की कामना की। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि देवों के देव महादेव की कृपा सदैव छत्तीसगढ़वासियों पर बनी रहे और प्रदेश निरंतर विकास एवं समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहे। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की।

देवी देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला पन्नालाल भेजे गए जेल

रायपुर। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवी-

देवताओं पर टिप्पणी करने वाले क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारी अरुण पन्नालाल को सीजेएम कोर्ट ने शनिवार को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है, वे 21 अगस्त तक जेल में रहेंगे। पन्नालाल ने जमानत याचिका भी दायर की थी जो खारिज कर दी गई। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवी-देवताओं पर टिप्पणी करने के बाद भाजपा के प्रवक्ता अमित चिमनानी ने क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारी अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिविल लाईन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिन्दू देवी-देवताओं को लेकर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और अरूण पन्नालाल को गिरफ्तार कर ले गई और आज कोर्ट में पेश किया जहां विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने के निर्देश दिए।

138 करोड़ की लागत से नांदघाट-मुंगेली रोड होगा फोरलेन

रायपुर। राज्य शासन ने बेमेतरा जिले के नांदघाट से मुंगेली जिला मुख्यालय तक पूर्व में स्वीकृत टू-लेन सड़क को फोरलेन करने 21 करोड़ 81 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। राज्य शासन ने वर्ष-2024 में सी.आर.आई.एफ. योजना के अंतर्गत टू-लेन नांदघाट-मुंगेली मार्ग के निर्माण के लिए 116 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने इस सड़क को टू-लेन से फोरलेन में परिवर्तित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे। उनके निर्देश के अनुपालन में नांदघाट-मुंगेली मार्ग के टू-लेन से फोरलेन में उन्नयन के लिए राज्य शासन ने गुरुवार को 21 करोड़ 81 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। पूर्व में स्वीकृत 116 करोड़ और गुरुवार को स्वीकृत 21 करोड़ 81 लाख को मिलाकर अब कुल 137 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से नांदघाट और मुंगेली के बीच 36.40 किमी फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री तथा नवागढ़ के विधायक श्री दयालदास बघेल ने नांदघाट-मुंगेली सड़क के फोरलेन के रूप में मंजूरी पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई दी है।

आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली का विस्तार भाटापारा-हथबंद सेक्शन में भी शुरू

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का रायपुर रेल मंडल रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित, तीव्र एवं दक्ष बनाने की दिशा में आधुनिक तकनीकों का निरंतर विस्तार कर रहा है। इसी क्रम में भाटापारा-हथबंद रेलखंड में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली सफलतापूर्वक प्रारंभ की गई है। इस तकनीकी उन्नयन से इस व्यस्त रेलखंड की संचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा ट्रेनों का संचालन पहले की अपेक्षा अधिक सुगम, सुरक्षित एवं समयबद्ध हो गया है। पूर्व में इस सेक्शन में इंटरमीडिएट ब्लॉक प्रणाली कार्यरत थी, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लागू होने के बाद अब इस सेक्शन में एक समय में अधिकतम ट्रेनों का संचालन संभव हो गया है। अर्थात बिना ट्रैक में किसी प्रकार का भौतिक परिवर्तन किए इस सेक्शन की क्षमता में वृद्धि हुई है।

एआई के जरिए जटिल से जटिल ऑपरेशन हो रहा आसानी से : रमन

रीढ़ की हड्डी जोडऩे में लग जाते है 8 से 10 लाख, श्री नारायणा में 50 मरीजों का हो रहा निःशुल्क ऑपरेशन सराहनीय : साव

रायपुर। श्री नारायणा हॉस्पिटल में तीन दिवसीय निःशुल्क मेगा स्पाइन एवं आर्थोपेडिक सर्जरी कैंप 2.0 का शुभारंभ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 वर्ष पहले जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस हॉस्पिटल का शुभारंभ किया और आज उन्होंने जरुरत 50 से अधिक मरीजों के होने वाले निःशुल्क ऑपरेशन का शुभारंभ कर रहे है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज विज्ञान इतना तेजी से विकास कर रहा है कि एआई के जरिए जटिल से जटिल ऑपरेशन भी आसानी से होने लगा है।

अच्छा लगता है जब स्वास्थ्य सुविधा का छत्तीसगढ़ में इतना तेजी से विकास हो रहा है और निश्चित रुप से इन 15 सालों में इस हॉस्पिटल ने बहुत से ऐसे काम किए है जो सराहनीय है। जब छत्तीसढ़ बना था उस समय इतना स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी लेकिन इन 26 सालों में छत्तीसगढ़ ने इतना विकास कर लिया है कि जगह-जगह पर हॉस्पिटल खुल गए है खासकर दूरस्त अंचलों में जहां अस्पतलों की बहुत जरुरत थी। श्री नारायणा हॉस्पिटल के द्वारा इससे पहले बीजापुर से मनेंद्रगढ़ तक के दूरस्त अंचलों में पहुंचकर वहां के गरीब मरीजों रोबोटिक स्पाइन सर्जरी व स्कोलियोसिस कर चुके है और आज यहां लगने वाला शिविर यह बताता है कि हॉस्पिटल गरीब मरीजों के इलाज करने में इतना गंभीर है कि वे इस सर्जरी को नि:शुल्क कर रहे है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हॉस्पिटल के 15 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जरूरतमंद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की यह सराहनीय पहल है। कैंप के माध्यम से रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, बच्चों में हड्डियों से संबंधित जन्मजात विकृतियों सहित विभिन्न सर्जरी निःशुल्क की जाएंगी। इस पहल के तहत 50 मरीजों की निःशुल्क सर्जरी के साथ दवाइयां एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराने के लिए 8 से 10 लाख रुपये लग जाते है और इतना बड़ी रकम का इंतजाम करने में गरीब मरीजों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है लेकिन श्री नारायणा में 50 मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन करने ही यह पहल सराहनीय है। इस दौरान मरीज व उनके परिजनों को फल वितरित कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत, विधायक मोतीलाल साहू, जगदलपुर के महापौर संजय पांडे, एक दैनिक अखबार के मुख्य संपादक, श्री नारायणा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ सुनील खेमका, मेडिकल डायरेक्टर डॉ मेघा खेमका, मुंबई के सीनियर स्पाइन सर्जन डॉ विशाल कुंदनानी के साथ देश के प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं हॉस्पिटल के स्टॉफ उपस्थित थे।

एम्स रायपुर के तृतीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन

- 2 सितंबर को होगा दीक्षांत समारोह, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगी शामिल

रायपुर। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर के तृतीय दीक्षांत समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह 2 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। एम्स रायपुर के कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अशोक जिंदल ने अपनी धर्मपत्नी उषा जिंदल के साथ नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। उपराष्ट्रपति ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की सहमति प्रदान की।

इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल जिंदल ने उपराष्ट्रपति को एम्स रायपुर द्वारा

पिछले वर्षों में रोगी सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, डिजिटल स्वास्थ्य और जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने संस्थान में रोबोटिक सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वास्थ्य अनुसंधान, जैव-चिकित्सकीय नवाचार तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों में हुई प्रगति से भी अवगत कराया। उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में एम्स रायपुर की भूमिका की सराहना की। उन्होंने आयुष्मान भारत तथा अन्य सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में संस्थान के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया।

तृतीय दीक्षांत समारोह एम्स रायपुर की शैक्षणिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशियलिटी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) तथा संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में उपाधियां प्रदान की जाएंगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगी। 2 सितंबर को आयोजित होने वाले इस दीक्षांत समारोह में अनेक गणमान्य अतिथियों, संकाय सदस्यों, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, पूर्व छात्रों तथा आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति रहेगी। समारोह एम्स रायपुर की स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में जारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पावर कंपनी में 1235 पदों पर होगी भर्ती

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ ने 1235 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें सहायक अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता और संयंत्र परिचारक से लेकर डाटा एंट्री आपरेटर, चिकित्सक,पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ऑफिसर्स व स्टाफ, विधि विभाग, वित्त अधिकारी, सुरक्षा विभाग तक के पद शामिल हैं। ये भर्तियां तीनों कंपनियों यथा जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में की जाएंगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उनके निर्देशानुसार पॉवर कंपनियों में बड़ी संख्या में की जा रही भर्ती से जहां एक तरफ बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं उपभोक्ताओं तक निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए मेनपावर भी उपलब्ध हो सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद यह पहला मौका है, जब इतनी अधिक संख्या में भर्तियां होंगी।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया को त्वरित गति से पूरा किया जाए। राज्य स्थापना के बाद प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या एवं बिजली खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य बनने के समय 18 लाख 91 हजार उपभोक्ता थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 67 लाख हो गई है। राज्य गठन के समय विद्युत की मांग 1334 मेगावाट थी, वह अब बढ़कर 7083 मेगावाट हो गई है। बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य शासन ने कोरबा पश्चिम में 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना करने का निर्णय लिया और इस हेतु कार्य भी प्रारम्भ हो गया है।साथ ही पारेषण और वितरण प्रणाली में भी बड़ी संख्या उपकेंद्र व लाइनें स्थापित की जा रही है। विद्युत संयंत्र, उपकेंद्रों तथा लाइनों के उचित रखरखाव एवं उपभोक्ताओं तक निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी संख्या में पॉवर कंपनियों में भर्ती करने का निर्णय किया गया है।

एटीएम से मिलेगा अनाज : रायपुर समेत 3 शहरों में ग्रेन एटीएम शुरू

दूसरे राज्य के हितग्राही भी कर सकेंगे इस्तेमाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को आधुनिक बनाने के लिए आज बड़ा कदम उठाया गया है। लोगों को राशन की दुकानों में लंबी लाइन लगाने से छुटकारा मिलेगा। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज राजधानी रायपुर समेत 3 शहरों में ग्रेन एटीएम का ऑनलाइन शुभारंभ किया।

मंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ग्रेन एटीएम की व्यवस्था की गई है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग से इसकी शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ देश का अब पांचवा राज्य बन गया है, जहां एटीएम से चावल निकाला जाएगा। न केवल छत्तीसगढ़ बल्की दूसरे राज्य जैसे उत्तराखंड, ओडिशा और यूपी के राशन कार्ड हितग्राही इस एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि 24 घंटे संचालित होने वाले ग्रेन एटीएम की सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे के साथ सभी एटीएम में गार्ड भी मौजूद रहेगा। 2500 किलोग्राम है। मशीन की क्षमता 2500 किलोग्राम है और इसमें चावल की लोडिंग भी स्वचालित होगी। लंब लाइन लगाने से छुटकारा मिलने के साथ ही हितग्राही अपनी सुविधा और समय के अनुसार कभी भी चावल ले सकेंगे।

धर्मांतरण के बड़े रैकेट का सरगना है पन्नालाल: चंद्राकर

रायपुर। भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी करने पर क्रिश्चन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी तो एक घटना मात्र हैं। दरअसल, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का अरुण पन्नालाल सरगना है, जिसकी पूरी हिस्ट्री जांचनी चाहिए।

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि अरुण पन्नालाल खुद कब धर्मांतरित हुए? कितने संस्थाओं से उन्हें पैसे मिले? इसका उपयोग कहां हुआ? आजीविका कैसे चल रही है? ऐसे सारे विषय में प्रशासन को जांच करना चाहिए। विदेशी फंडिंग के यहां के सरगना हैं पन्नालाल। मैं मांग करता हूं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच की जाए।

वहीं अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बजरंग दल और आरएसएस के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इसकी निंदा करती है। सरकार के लोगों को इस पर आत्म अवलोकन करना चाहिए। धर्म स्वातंर्त्य विधेयक को लेकर लोगों को उकसाकर कार्रवाई कर रहे हैं,

हिंदुस्तान सभी लोगों का है, यहां संत महात्माओं का आदर है।

ट्रेनिंग के बाद अब कांग्रेस जिलाध्यक्षों को पार्टी हाईकमान के रैंकिंग देने पर अजय चंद्राकर ने कहा कि राहुल गांधी के पास अभी समय नहीं हैं। वो सोशल मीडिया में पेट्रोलियम गाड़ी का ढक्कन खोलने, बंद करने में व्यस्त हैं, ऐसे में रैंकिंग के लिए समय कहां होगा।

उन्होंने कहा कि रैंकिंग की बात फर्जी समाचार है, ऐसा मुझे लगता है। दरअसल, कांग्रेस के पास ना कार्यकम है, ना उद्देश्य है, और ना ही विजन है। किसी तरह से अपने चले आ रहे कैडर को व्यस्त रखना है। तो उठक-बैठक कराते रहते हैं, और कुछ नहीं है।

अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा में दूध में मक्खी की तरह निकाले दिए गए हैं अजय चंद्राकर। वे उललू-जुलूल बात करते हैं। ई20 पेट्रोल का मुद्दा आमजनता की समस्या है। अजय चंद्राकर को ये खराब लग रहा है, क्योंकि उनके आंखों में चाटुकारिता की पट्टी बांधी है। सत्ता में रहने के कारण भाजपा को कैडर बेस पार्टी बोली जाती रही है, पर उनमें कैडर ही नहीं बचा है।

रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने को लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के पत्र को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि उन्होंने जो पत्र लिखा है, वह मैने भी पढ़ा है। नई व्यवस्था को सेट होने में टाइम लगेगा। रायपुर को टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए। कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत पूरे शहर को रखना चाहिए।

कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर बृजमोहन अग्रवाल की चिट्ठी पर अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा कि कमिश्नर प्रणाली राज्य सरकार की विफलता की उपज है। कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद अपराध बढ़े हैं। पुलिस ने एफआईआर लिखना बंद कर दिया है। कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद अपराधों में अंकुश नहीं लगा है, कांग्रेस दोनों ही नेताओं से सहमत है। कमिश्नरेट लागू होने से सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं।

मातृशक्ति के खातों में पहुँची महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त

महतारी वंदन योजना मातृशक्ति के सम्मान, आत्मनिर्भरता और परिवारों की समृद्धि का अभियान: साय

- मुख्यमंत्री ने 67.20 लाख माताओं और बहनों के खातों में अंतरित किए 630.55 करोड़ रुपये

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 67 लाख 20 हजार 125 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 630 करोड़ 55 लाख 54 हजार 300 रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार तथा संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना राज्य सरकार की उन प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन

प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि जब माताएं और बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तब परिवार मजबूत होता है, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है और समाज विकास की नई दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए मातृशक्ति का सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह योजना केवल प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन चुकी है। प्रदेश के लाखों परिवारों में यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग हो रही है, जिससे महिलाओं की आर्थिक भूमिका और अधिक सशक्त हुई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अनेक महिलाएं महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि का सदुपयोग करते हुए अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रही हैं। कई माताएं अपनी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में नियमित निवेश कर रही हैं। वहीं बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, किराना दुकान, सब्जी विक्रय, पशुपालन, अगरबत्ती निर्माण तथा अन्य छोटे स्वरोजगार शुरू कर अपनी आय बढ़ाई है। इससे वे न केवल परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी प्रस्तुत कर रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। महतारी वंदन योजना इसी सोच का परिणाम है, जिसमें हर महीने बिना एक हजार रुपए की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। डीबीटी व्यवस्था ने पारदर्शिता बढ़ाई है और महिलाओं में शासन के प्रति विश्वास भी मजबूत किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वरोजगार, कौशल विकास तथा वित्तीय समावेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही है। महतारी वंदन योजना इन सभी प्रयासों का महत्वपूर्ण आधार बनकर महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान प्रदान कर रही है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सुकमा, (छत्तीसगढ़)
Ph& Faz No. 07864-284401,
Email ID-deo.sukmaw012@gmail.com, rmsa.sukma@gmail.com

क्रमांक 1634/जि0शि0अ0/EGL/2026-27 सुकमा, दिनांक 31.07.2026

// निविदा सूचना//

जिला प्रशासन, सुकमा के द्वारा 345 EGL प्राथमिक शालाओं के बच्चों में भाषा सीखने मे आ रही दिक्कतों को समझते हुए कक्षा 1ली एवं 2 री में विद्यार्थियों की भाषा दक्षता एवं प्रारंभिक साक्षरता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से EGL (EARLY GRADE LITERACY) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। जिसमें EGL कक्षा का प्रभावी संचालन एवं सहयोग, EGL कक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास करना, एवं EGL कार्यक्रम का नियमित मॉनिटरिंग, फिल्ड विजिट, प्रगति रिर्पोट समीक्षा दस्तावेजीकरण एवं मूल्यांकन कार्य किया जाना हैं। तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत अकादमिक संस्था को 07 माह के लिए कार्यक्रम संचालन एवं निगरानी हेतु 12 समन्वयक नियुक्त हेतु अनुबंधित किया जाना है जिस हेतु मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला सुकमा से निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन दिवस व समय में आकर राशि 500.00 रूपये जमा कर निविदा आवेदन प्राप्त किये जा सकते है।

निविदा फार्म विक्रय की अंतिम तिथि	30/08/2026 सायं 5.30 बजे तक।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	31/08/2026 अपराह्न 2.00 बजे तक।
निविदा खोलने की तिथि	31/08/2026 अपराह्न 2.00 बजे।
साक्षात्कार एवं प्रस्तुतिकरण तिथि	31/08/2026 अपराह्न 3.00 बजे से।

जी-262702614/4

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला - सुकमा

क्या टूटने वाला है संसद में जारी गतिरोध?

शशिधर पाठक

अगले सप्ताह संसद में सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध टूटने के आसार हैं। 12 अगस्त को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में एफसीआरए संसोधन विधेयक-2026 पेश कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले विपक्ष गृहमंत्री को सदन में बुलाने की पूरी जोर अजमाइश कर रहा है। सभापति सीपी राधाकृष्णन के एक दिशा-निर्देश ने उसे मानो संजीवनी दे दी। शुक्रवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्य अपनी बात रख रहे थे। विपक्ष के सांसद पवन खेड़ा समेत अन्य सदस्य केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बुलाने, 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए बल प्रयोग पर जवाब देने की मांग पर अड़े थे। विपक्षी सदस्यों के हंगामे, नारेबाजी शोर-शराबे के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने आसन से इसे गंभीरता से लेने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री के सदन में न आने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम आसन से अनुरोध करते हैं कि वह गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देने का निर्देश दें। खरगे ने कहा कि विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार है। खरगे ने विपक्ष के व्यवधान को जायज बताया और कहा कि जब हम जायज सवाल पूछ रहे हैं तो वह बच रहे हैं। इससे पहले भी खरगे ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा था कि आखिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों छिप रहे हैं। उन्हें सदन में आकर जवाब देना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन का सदन संचालन का कौशल विपक्ष को भी अच्छा लगता है। उन्होंने खरगे को सुनने के बाद संसदीय कार्यमंत्री से कहा कि वह विपक्ष की भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं। हालांकि सभापति ने कहा कि इस बारे में गृह मंत्री को ही निर्णय लेना है कि वह सदन में बयान देंगे अथवा नहीं। सभापति सीपी राधाकृष्णन के इस दिशा निर्देश का संदेश काफी दूर तक जाने की दृष्टि से देखा जा रहा है। सभापति के इस निर्देश पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट करते हुए उम्मीद जताई कि संसदीय कार्यमंत्री सभापति के निर्देश का पालन करेंगे। संसदीय कार्यमंत्री इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर आपत्ति जताई और नियम 335(2) और 240 का हवाला देते हुए कहा कि हर दिन खरगे जी वही बात पढ़ते हैं, वही बात कहते हैं। यह नियम हमारे विपक्ष के नेता पर लागू नहीं होता है। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के सदस्य सदन में आते हैं। दिन भर सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते। शोर-शराबा करते हैं। नारा लगाते हैं और संसद के कामकाज में रुकावट डालकर चले जाते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री जी मानसून सत्र के दौरान हर रोज संसद आते हैं। वह सुबह से लेकर देर शाम तक संसद भवन में रहते हैं। अपना काम करते हैं। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि आसन से सरकार को गृह मंत्री को सदन में बुलाने जैसा कोई निर्देश नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष नहीं तय करेगा कि कौन मंत्री सरकार की तरफ से बोलेगा या सदन में बयान देगा। यह सरकार का काम है कि वह किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी सौंपेगी। खरगे ने पत्रकारों से भी बात के दौरान कहा कि विपक्ष की मांग जायज है। वह गृहमंत्री और प्रधानमंत्री से सदन में आकर बयान देने की मांग कर रहे हैं। ये सरकार के नियंत्रण में हैं। सरकार इसे बहुत आसानी से कर सकती है। खरगे ने कहा कि जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को इतनी गंभीर घटना हुई है। फिर भी गृहमंत्री इस पर बयान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।

उपचुनावों का जनादेश: क्या बदल रहा है मतदाता का मिजाज?

योगेश कुमार गोयल

लोकतांत्रिक राजनीति में कई बार छोटे चुनाव भी बड़े संदेश दे जाते हैं। विधानसभा उपचुनावों को लंबे समय तक केवल रिक्त सीटों को भरने की औपचारिक प्रक्रिया माना जाता रहा है। सामान्य धारणा यही रही कि जिस राज्य में जिस दल की सरकार होती है, प्रशासनिक बढ़त, संगठनात्मक शक्ति और सत्ता के प्रभाव के कारण वही दल उपचुनाव आसानी से जीत जाता है। इसी कारण उपचुनावों के परिणामों को व्यापक राजनीतिक संकेतक के रूप में कम ही देखा जाता था किंतु पिछले कुछ वर्षों में यह धारणा तेजी से बदली है। अब उपचुनाव केवल एक सीट का फैसला नहीं करते बल्कि जनता के तत्कालीन मनोभाव, सरकार के प्रति संतोष-असंतोष, संगठन की मजबूती, नेतृत्व की स्वीकार्यता और भविष्य की राजनीतिक दिशा के संकेत भी देते हैं। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांझलपुर विधानसभा उपचुनावों ने भी यही संदेश दिया है। तीन सीटों में से दो पर भाजपा की हार और केवल एक पर जीत ने राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या ये केवल स्थानीय परिस्थितियों का परिणाम हैं अथवा भाजपा के सामने उभर रही नई राजनीतिक चुनौतियों का प्रारंभिक संकेत? उपचुनाव सत्ता परिवर्तन का जनादेश नहीं होते किंतु वे जनता के बदलते मानस की पहली आहट अवश्य होते हैं और यही कारण है कि इन परिणामों को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है।

सबसे अधिक चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की रही। यह सीट केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं थी बल्कि भाजपा की राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। लगभग तीन दशक से यह भाजपा का अभेद्य दुर्ग रहा। पहले भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन के पिता और बाद में स्वयं नितिन नवीन लगातार यहां विजय प्राप्त करते रहे। नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह सीट रिक्त हुई और भाजपा को अटूट विश्वास था कि उसका यह गढ़ सुरक्षित रहेगा किंतु जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने न केवल भाजपा का यह किला ध्वस्त कर दिया बल्कि बिहार की राजनीति में नए विकल्प की संभावनाओं को भी मजबूत कर दिया। यह परिणाम केवल भाजपा की हार नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक चूक का भी परिणाम माना जा

रहा है। उम्मीदवार चयन में अंतिम समय तक बना भ्रम, स्थानीय कार्यकर्ताओं की असंतुष्टि और अत्यधिक आत्मविश्वास ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। लंबे समय तक किसी सीट पर लगातार जीत कभी-कभी संगठन में आत्मसंतोष पैदा कर देती है। यही स्थिति बांकीपुर में दिखाई दी। भाजपा ने शायद मान लिया था कि उसका पारंपरिक वोट बैंक और संगठनात्मक नेटवर्क किसी भी परिस्थिति में जीत सुनिश्चित कर देगा जबकि मतदाता पहले की तुलना में अधिक सजग और स्वतंत्र निर्णय लेने वाला बन चुका है। बांकीपुर का परिणाम प्रशांत किशोर के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में अनेक दलों को सफलता दिलाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार स्वयं चुनावी परीक्षा में उतरे और सफल हुए। हालांकि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरी तरह विफल रही थी किंतु इस विजय ने सिद्ध कर दिया कि यदि कोई दल लगातार जनता के बीच बना रहे और स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाए तो वह स्थापित राजनीतिक समीकरणों को चुनौती दे सकता है। यह जीत बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं को भी बल देती है।

दूसरी ओर मध्य प्रदेश की दतिया सीट भाजपा के लिए और अधिक चिंता का विषय है। भाजपा की यह हार केवल विपक्ष की सफलता नहीं बल्कि भाजपा संगठन के भीतर असंतोष की अभिव्यक्ति भी मानी जा रही है। पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद उनके समर्थकों की नाराजगी चुनाव अभियान के दौरान लगातार चर्चा में रही। चुनावी राजनीति में उम्मीदवार केवल पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होता बल्कि स्थानीय संगठन की भावनाओं का केंद्र भी होता है। जब कार्यकर्ता स्वयं उत्साहहीन हो जाएं या भीतरघात की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो मजबूत संगठन भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाता। दतिया का परिणाम इसी सत्य की पुष्टि करता है। मध्य प्रदेश भाजपा लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अत्यंत मजबूत संगठनात्मक ढांचे के लिए जानी जाती रही। संगठन, सरकार और जनता के बीच संवाद की जो परंपरा विकसित हुई थी, नेतृत्व परिवर्तन के बाद उसे उसी प्रभावशीलता से बनाए रखना नई सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। उपचुनावों ने संकेत दिया है कि केवल सत्ता में होना पर्याप्त नहीं, संगठन की एकजुटता और स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता भी उतनी ही आवश्यक है।

गुजरात के मांझलपुर में भाजपा ने जीत दर्ज कर अपनी संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन अवश्य किया किंतु मतों के अंतर में आया परिवर्तन संकेत देता है कि वहां भी विपक्ष धीरे-धीरे अपनी जमीन मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि गुजरात में भाजपा की स्थिति अभी भी सुदृढ़ है, फिर भी चुनावी आंकड़े बताते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए आत्मसंतोष उचित नहीं हो सकता। इन उपचुनावों की चर्चा का एक महत्वपूर्ण पक्ष 'जेन-जी आंदोलन' भी रहा। चुनाव 30 जुलाई को ऐसे समय हुए, जब प्रतियोगी परीक्षा, पेपर लीक, रोजगार, अवसरों की कमी, प्रशासनिक जवाबदेही इत्यादि युवाओं से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में थे। निश्चित रूप से यह कहना कठिन होगा कि केवल इसी आंदोलन ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया क्योंकि प्रत्येक उपचुनाव में स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की लोकप्रियता और संगठनात्मक स्थिति कहीं अधिक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि युवाओं के बीच बढ़ती असंतुष्टि का व्यापक राजनीतिक वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। यदि युवा मतदाता किसी सरकार के प्रति निराशा महसूस करता है तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव चुनावी व्यवहार पर भी दिखाई दे सकता है। आज का मतदाता (विशेषकर युवा वर्ग) केवल जातीय या पारंपरिक राजनीतिक पहचान के आधार पर मतदान नहीं कर रहा, रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, सुशासन, अवसरों की समानता और प्रशासनिक उत्तरदायित्व जैसे मुद्दे उसकी प्राथमिकता बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल संचार ने भी मतदाता को पहले से अधिक जागरूक बनाया है। अब सरकारों के लिए केवल विकास के दावे पर्याप्त नहीं, उनके ठोस परिणाम भी दिखाई देने चाहिए। अखबार

भाजपा के लिए इन परिणामों से सबसे बड़ा सबक उम्मीदवार चयन को लेकर है। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में देखा गया है कि टिकट वितरण को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष उत्पन्न हुआ है। संगठन की राय, कार्यकर्ताओं की भावनाओं और स्थानीय लोकप्रियता की उपेक्षा कभी-कभी चुनावी नुकसान का कारण बन जाती है। यदि पार्टी समय रहते इस पहलू पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो भविष्य के बड़े चुनावों में भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। भाजपा को यह भी समझना होगा कि कोई भी राजनीतिक गढ़ स्थायी नहीं होता। लोकतंत्र में जनता समय-समय पर अपने निर्णय बदलती है और वही दल लंबे समय तक सफल रहता है, जो निरंतर आत्म-मूल्यांकन करता रहे। उपचुनावों ने भाजपा को यही संदेश दिया है कि संगठन की मजबूती, नेतृत्व की विश्वसनीयता और जनता के साथ सतत संवाद बनाए रखना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। हालांकि इन परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि राष्ट्रीय राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल रहा है। तीन विधानसभा सीटों के परिणाम किसी सरकार की लोकप्रियता का अंतिम पैमाना नहीं हो सकते, फिर भी लोकतंत्र में छोटे संकेतों की उपेक्षा करना भी राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता क्योंकि यही छोटे संकेत आगे चलकर बड़े राजनीतिक परिवर्तनों की भूमिका तैयार करते हैं।

विपक्ष के लिए ये परिणाम आशा का संदेश हैं किंतु यह आशा तभी सार्थक होगी, जब वह केवल सत्ता विरोधी वातावरण पर निर्भर रहने के बजाय विश्वसनीय नेतृत्व, स्पष्ट वैकल्पिक नीति और मजबूत संगठन प्रस्तुत कर सके। वहीं जन सुराज जैसे नए राजनीतिक दलों के लिए यह अवसर भी है और परीक्षा भी। एक सीट की सफलता को व्यापक जनविश्वास में बदलना कहीं अधिक कठिन कार्य होगा। इन उपचुनावों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि मतदाता पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक, अधिक अपेक्षाकारी और अधिक स्वतंत्र निर्णय लेने वाला हो चुका है। अब चुनाव केवल संगठनात्मक शक्ति या पुराने राजनीतिक समीकरणों से नहीं जीते जा सकते। जनता नेतृत्व की विश्वसनीयता, उम्मीदवार की स्वीकार्यता, स्थानीय मुद्दों के समाधान और भविष्य की स्पष्ट दृष्टि को भी उतना ही महत्व देती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति अंतत: जनता ही होती है और जनता समय-समय पर छोटे चुनावों के माध्यम से भी बड़े संदेश देना कभी नहीं भूलती।

पुराण दिग्दर्शन ....

विश्व विद्या-निरुपणाध्याय: (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

अत: हमारी इस पृथ्वी का परिमाण पचास करोड़ योजन मानना युक्ति और प्रत्यक्ष दोनों के ही प्रतिकूल दीख पड़ता है।

परन्तु शिवपुराण में लिखा है-

पंचाशत् कोटिविस्तीर्णा सशैलवनकानना।

(विद्येश्वर संहिता 12 12)

अर्थात् - यह भूमि-पवंत वन प्रादि सहित पचास करोड़ योजन परिमाण वाली है। इत्यादि।

उपर्युक्त आक्षेप को पढ़कर पाठक अवश्य शङ्कित हो जायेंगे। एक हद् तक शङ्कित हो जाना कुछ स्वाभाविक सा भी जंचता है। परन्तु है यह शङ्का निर्मूल! तिनके की ओट में हिमालय छुपा हुआ। आइए हम आपको एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। कल्पना कीजिए कि हम कुछ सज्जनों से एक गोलमटोल गेंद का परिमाण दर्याफ्त करते हैं। एक सज्जन उसका परिमाण निकालने के लिए एक सूत का धागा लेकर गेंद के उपरि भाग के ठीक बीचों बीच एक छोर से दूसरे छोर तक नाप कर धागे की लम्बाई के अनुसार परिमाण बताते हैं। दूसरे साहिब एक लोहे की लम्बी सलाई लेकर उससे गेंद को बीचों बीच छेदते हुये [सलाई का जितना भाग दोनों पड़तों के बीत्त में समा गया था उसकी लम्बाई के अनुसार गेंद का परिमाणण ठहराते हैं। तीसरे महानुभाव गेंद के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल निकाल कर उससे ही गेंद का परिमाण निश्चित करते हैं। इस तरह गेंद का परिमाण बताने वाले तीनों सज्जनों के आँकड़े तो पृथक् 3 होंगे परन्तु तात्पयं तीनों का एक ही होगा। इसके अतिरिक्त विद्वान् लोगों की दृष्टि में सूत के धागे से नापने वाले, लोहे की शलाका से मिनने वाले उत्तरदाताओं की अपेक्षा गणित द्वारा गेंद का घनफल (रकबा) बताने वाला महानुभाव ही अधिक प्रतिष्ठापात्र होगा, क्योंकि उसने गेंद का परिमाण निकालने में अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया है।

क्रमश: ...

विश्व आदिवासी दिवस

डॉ. मन्ना लाल रावत

हमारे जीवन में त्योहारों और उत्सवों का बड़ा महत्व है और भारतीय संस्कृति को तो त्यौहार और उत्सवों की संस्कृति रूप ही जाता है। जनजाति समाज के बंधु-भगिनियों में स्वाभाविक रूप से संस्कृति के सभी पक्षों से लगाव रहा है जो हमारी एक प्रमुख पहचान भी है। इसके माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखते हैं, परंतु विगत 2-3 वर्षों से एक नई प्रवृति आई है जिसे 9 अगस्त यानि विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाये जाने के रूप् में देख सकते हैं। यह आयोजन बिना ऐतिहासिक सत्यता जाने और बिना भारत के संदर्भ के होने लगा है। हद तो ये है कि इसमें कई बुद्धिजीवी भी सम्मिलित होने लगे और शासन स्तर पर कुछ लोक लुभावने नीतिगत निर्णय भी होने लगे परंतु

भारत गणराज्य के रूप में इस दिन की सत्यता को जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह प्रश्न मात्र जनजाति समाज-संस्कृति का ही नहीं है बल्कि देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी कीमती हो जाता है।

हमें याद है कि मध्य काल में भौगोलिक खोजों के दौरान स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं ने कैसे अग्रणी प्रयास किए। इस दौर में कैथोलिक मिशन की आर्थिक मदद से भारतवर्ष के व्यापार मार्ग खोजने के उद्देश्य से एक नाविक कोलंबस को समुद्री मिशन पर भेजा गया जिसके द्वारा भूलवश 12 अक्टूबर, 1492 को नई दुनिया की खोज की गई। नई दुनिया कुछ और नहीं, बल्कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट था। इस काल खण्ड में पुरे अमेरिकी महाद्वीप पर मूल निवासियों का अधिपत्य था जिसमें चेरोकी, चिकासौ, चोक्ताव, मास्कोगी और सेमिनोल प्रमुख थीं। इन सभी मूलनिवासियों को कोलंबस ने इंडियन कहा। कोलंबस की खोज के बाद धीरे-धीरे यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका में अपना साम्राज्य फैलाने की पूरी रूपरेखा तैयार की और सबसे पहले यहां के मूल निवासियों से संघर्ष करना पडा। इस क्रम में सबसे पहला युद्ध वर्जिन्या प्रांत में पवहाटन आदिवासियों से करना पड़ा। तीन युद्ध की इस श्रृंखला में पहला युद्ध 9 अगस्त 1610 को हुआ जिसमें पवहाटन कबीले के सभी सदस्य युद्ध करते हुए मारे गए। यह युद्ध भारतीय इतिहास के संदर्भ में अंग्रेजों के विरूद्ध सन् 1757 में प्लासी के युद्ध के समान माना जाता है। इस युद्ध की जीत के साथ ही अंग्रेजों को अमेरिका के आदिवासियों को पूरी तरह से खत्म करने का रास्ता खोल दिया।

त्रासदी भरी इस यात्रा में 'आंसुओं की रेखा' व 'धर्म प्रचार की शुरुआत करने के दिवस' को भी जानना आवश्यक है।

इस बात के समय में लगभग 250 वर्षों में अमेरिका के मूल निवासियों का भारी रक्तपात करके भी यूरोपीय शक्तियां केवल थोड़े से भैगोलिक भूभाग पर ही अपना आधिपत्य जमा सकी थीं, तब जॉर्ज वाशिंगटन और हन्री नॉक्स के नेतृत्व में पहला ब्रिटिश-अमेरिकी युद्ध शुरू हुआ। इस संघर्ष में 30,000 स्थानीय मूल निवासियों (आदिवासीजन) रास्ते में ही मर-खप गए।

श्रीलंका के साथ भारत रिश्तों को दे रही नया रूप

अरुणिम भूयान

श्रीलंका के साथ भारत की बढ़ती डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हिंद महासागर में चीन के साथ रणनीतिक मुकाबले में एक अहम हथियार के तौर पर उभर रही है। नई दिल्ली अब मानवीय मदद से आगे बढ़कर कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक एकीकरण जैसे क्षेत्रों में लंबे समय के निवेश पर ध्यान दे रही है।

चार दिन पहले बुधवार को विदेश सचिव विक्रम मिसरी की कोलंबो यात्रा के नतीजे बताते हैं कि भारत श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही, वह बीजिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर-केंद्रित नजरिए के मुकाबले विकास का एक वैकल्पिक मॉडल भी पेश कर रहा है।चीन के साथ-साथ भारत भी श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय डेवलपमेंट पार्टनर बना हुआ है।

भारत की मदद में ग्रांट (अनुदान), रियायती दरों पर क्रेडिट लाइन, क्षमता-निर्माण कार्यक्रम और मानवीय सहायता शामिल हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट और उसके बाद आई प्राकृतिक आपदाओं के बाद से, नई दिल्ली ने अपनी %नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी% और %विजन महासागर% (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) के तहत विकास सहयोग का दायरा बढ़ाया है। इसमें कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थकेयर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

श्रीलंका स्थित थिंक टैंक %एशियन जियोपॉलिटिक्स, सस्टेनेबिलिटी एंड पीस काउंसिल% के महासचिव सुगीश्वर सेनाधिरा ने कहा कि ग्रांट के अलावा, भारत एक प्रतिशत ब्याज और तीन साल की ग्रेस अवधि वाले आसान लोन (सॉफ्ट लोन) भी देता है।कोलंबो से फोन पर ईटीवी भारत से बात करते हुए सेनाधिरा ने कहा, चीन सिर्फ कमर्शियल लोन देता है। सेनाधिरा चार पूर्व राष्ट्रपतियों और एक प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार

भी रह चुके हैं।

उन्होंने कहा कि पेरिस क्लब (सरकारी कर्ज देने वाले देशों का एक अनौपचारिक समूह) और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलने वाले लोन के साथ भी कड़ी शर्तें जुड़ी होती हैं।सेनाधिरा ने कहा, इसलिए, भारत की शर्तें अधिक स्वीकार्य हैं। श्रीलंकाई लोग भारत के विकास सहयोग को बहुत सकारात्मक नजरिए से देखते हैं।

कोलंबो की अपनी यात्रा के दौरान, मिसरी ने दोनों पक्षों के साथ कई अहम प्रोजेक्ट्स पर हुई प्रगति की समीक्षा की। ये प्रोजेक्ट्स या तो अभी चल रहे हैं या जल्द ही शुरू होने वाले हैं।भारत की मदद से चल रहे सबसे बड़े प्रोग्राम्स में से एक है 450 मिलियन डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज, जिसकी घोषणा श्रीलंका में चक्रवात %दितवाह% से हुई भारी तबाही के बाद की गई थी।इस पैकेज में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण के लिए ग्रांट (अनुदान) और रियायती दरों पर लोन, दोनों शामिल हैं।

यात्रा के दौरान जिन कामों की प्रगति की समीक्षा की गई, उनमें क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण, पक्के पुलों का निर्माण, सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाने वाले उपाय शामिल हैं।

भारत और श्रीलंका ने हाल ही में भारतीय रुपये में रियायती क्रेडिट लाइन की दो अहम व्यवस्थाएं भी शुरू की हैं।250 मिलियन डॉलर की रेलवे क्रेडिट लाइन से रेलवे के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। इसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत, ट्रैक को अपग्रेड करना, रेलवे के उपकरण खरीदना और यात्री व माल ढुलाई सेवाओं में सुधार जैसे काम शामिल हैं।

भारत ने श्रीलंका के रेलवे नेटवर्क के पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है, खासकर गृह युद्ध के बाद उत्तरी प्रांत में।भारत की ओर से दी गई एक और 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन से पशुपालन विकास, खेती से जुड़ी जरूरतों और श्रीलंका द्वारा पहचाने गए अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मदद मिलेगी।

ऊर्जा सहयोग भारत-श्रीलंका रणनीतिक साझेदारी के मुख्य स्तंभों में से एक बन गया है। प्रस्तावित समुद्र के नीचे का ट्रांसमिशन लिंक भारत और श्रीलंका के पावर ग्रिड को जोड़ेगा, जिससे सीमा-पार बिजली व्यापार संभव होगा, ऊर्जा सुरक्षा बेहतर होगी और रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) को अपनाने में आसानी होगी।

इस प्रोजेक्ट को क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग के लिए क्रांतिकारी माना जा रहा है।पूर्वी श्रीलंका में लंबे समय से लंबित संपूर सोलर प्रोजेक्ट को नए सिरे से राजनीतिक समर्थन मिलने के बाद आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके उद्देश्यों में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन बढ़ाना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और श्रीलंका के स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने में मदद करना शामिल है।

भारत और श्रीलंका मिलकर त्रिंकोमाली को क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र (हब) के रूप में विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं।इस प्रोजेक्ट में तेल भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और बंदरगाह से जुड़ी ऊर्जा सेवाएं शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी में त्रिंकोमाली की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, इस पहल का आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्व है।

दोनों पक्षों ने कांकेसंथुराई बंदरगाह प्रोजेक्ट के पुनर्वास और आधुनिकीकरण पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए जल्द से जल्द बातचीत शुरू करने का निर्देश भी दिया। इसे 61।5 मिलियन डॉलर की ग्रांट (अनुदान) के तहत लागू किया जाएगा।

अपग्रेड किए गए बंदरगाह से उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी भारत के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने, व्यापार को बढ़ावा मिलने, पर्यटन को बढ़ावा मिलने और क्षेत्रीय समुद्री कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।

भारत, श्रीलंका में एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने में भी मदद कर रहा है।इस प्रोजेक्ट का मकसद सुरक्षित डिजिटल पहचान बनाना, सरकारी सेवाओं की डिलीवरी बेहतर करना, फाइनेंशियल इन्क्लूजन को बढ़ावा देना और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना है।

हेल्थकेयर, श्रीलंका के साथ भारत की सबसे मजबूत डेवलपमेंट पार्टनरशिप में से एक है।विदेश मंत्रालय के अनुसार, डेनियाया अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई (जिसके लिए 13 जुलाई को रूश साइन किया गया था) और श्रीलंका में मेडिकल कियोस्क की सप्लाई के मामले में भी प्रगति हुई है।

श्रीलंकाई सरकार डेनियाया अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है क्योंकि इसकी मौजूदा लोकेशन आपदा-संभावित इलाके में है।अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम तीन साल में पूरा होने का अनुमान है, जिसमें इक्विपमेंट की डिलीवरी और इंस्टॉलेशन का काम कंस्ट्रक्शन के आखिरी चरणों के साथ-साथ किया जाएगा।

इस प्रोजेक्ट का मकसद दक्षिणी श्रीलंका में हेल्थकेयर तक पहुंच को बेहतर बनाना है।भारत, प्राइमरी हेल्थकेयर डिलीवरी को मजबूत करने के लिए पूरे श्रीलंका में मेडिकल कियोस्क लगाने में भी मदद कर रहा है।विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, अप्रैल 2025 में भारत के प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा के दौरान किए गए वादे को याद करते हुए, दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि 1990 सुवा सेरिया एम्बुलेंस सर्विस के प्रस्तावित विस्तार को लागू करने के लिए रूश जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

आज का इतिहास

1683 एक आदेश के जरिए ब्रिटिश राजशाही ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में युद्ध अथवा शांति की घोषणा का अधिकार दिया।
1788 गुलाम कादिर ने दिल्ली के सुलतान शाह आलम द्वितीय की आंख में अपना खंजर घोंपकर उसे अंधा कर दिया। 1831 = अमेरिका में पहली बार स्टीम इंजन ट्रेन चली।
1892 थॉमस अल्वा एडिसन ने टू-वे टेलिग्राफ का पेटेंट कराया।
1925 क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन लूट ली। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था।
1942 महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया।
1925 9 अगस्त को बहु प्रसिद्ध काकोरी काण्ड की घटना घटित हुई थी।
1945 अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया।
1971 भारत-पाकिस्तान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर।
1999 रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने प्रधानमंत्री सर्जेई स्तेपशिन को बर्खास्त कर खुफिया सेवा के प्रमुख ब्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
2000 जिम्बाब्वे में व्यापक विरोध के बावजूद भूमि सुधार की प्रक्रिया शुरू।
2002 पाकिस्तान में एक मिशनरी अस्पताल पर फिदायीन हमला, पांच व्यक्ति मारे गये, अफ़ग़ानिस्तान के जलालाबाद शहर में एक बम विस्फोट में 50 लोग मारे गये।
2005 नासा का मानवयुक्त अंतरिक्षयान डिस्कवरी 14 दिन की अपनी साहसिक और जोखिम भरी यात्रा के बाद कैलिफ़ोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल उतरा।
2006 नेपाल सरकार और माओवादियों के बीच संयुक्त राष्ट्र निगरानी मुद्दे पर सहमति बनी।
2007 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मरम्मत के महत्त्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम लेकर अंतरिक्ष यान एण्डेवर अपने अभियान पर निकला।
2008 सरकारी क्षेत्र की तीन कंपनियाँ एनटीपीसी, एनएचपीसी व पावर फाइनेन्स कारपोरेशन तथा टाटा कन्सल्टेन्सी ने राष्ट्रीय स्तर पर पावर एक्सचेंज गठित करने तथा उसके संचालन हेतु एक संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये।
2008 भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के समर्थन से मलेशिया के सांस्कृतिक मंत्री व सांसद मोहम्मद शफी अरदाल को राष्ट्रकुल संसदीय संघ (सीपीए) का नया अध्यक्ष चुना गया है।
2012 भारतीय सेना ने 9 अगस्त, 2012 को परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि-2 बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

जुबान बिगड़ी हुई थी उदयनिधि की, पहली बार मिला उसे सवा शेर

अभिनय आकाश

1989 की 25 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा था। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके ने हाल के ही विधानसभा चुनाव में 27 सीटें जीती थीं और तमिलनाडु की विधानसभा को विपक्ष में एक महिला नेता मिली थी। उस वक्त डीएमके सरकार में थी और मुख्यमंत्री थे एम करुणानिधी। सदन में जैसे ही बजट भाषण पढ़ा जाना शुरू हुआ जयललिता और उनकी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि एआईएडीएमके के किसी नेता ने करुणानिधी की तरफ फाइल फेंकी जिससे उनका चश्मा गिरकर टूट गया। जयललिता ने जब देखा कि हंगामा ज्यादा बढ़ रहा है तो वो सदन से बाहर जाने लगी। तभी मंत्री दुरई मुरगन आ गए और उन्होंने जयललिता को बाहर जाने से रोका और उनकी साड़ी खींची जिससे उनकी साड़ी फट गई और वो खुद भी जमीन पर गिर गईं। सत्ता पक्ष यानी डीएमके और विपक्ष यानी एआईएडीएमके के सदस्यों के बीच विधानसभा में हाथा-पाई हुई। अपनी फटी हुई साड़ी के साथ जयललिता विधानसभा से बाहर आ गईं। यही वो दिन था जब जयललिता ने सदन से निकलते हुए कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनकर ही इस सदन में वापस आएंगी वरना कभी नहीं आएंगी।कई बार जिंदगी में हुई घटना बहुत कुछ बदलकर रख देती है। कई बार इतिहास की घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब एक बार फिर तमिलनाडु की राजनीति में एक महिला का नाम चर्चा में है। इस बार विवाद अभिनेत्री तृषा कृष्णन से जुड़ा है। बयान जो सीधे तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के लिए था लेकिन इसमें नाम जुड़ा है एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन का भी। पूरा मामला समझ लेते हैं।

3 अगस्त 2026 यानी बीते सोमवार की बात है। जब सुर्खियों में बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव के परिणामों की चर्चा थी तब तमिलनाडु के थंजाऊर में किसानों का एक प्रदर्शन चल रहा था। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है। कावेरी नदी का पानी कर्नाटक से होकर तमिलनाडु पहुंचता है। तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक की सरकार पानी ही नहीं छोड़ती। जिसकी वजह से राज्य के किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई के लिए

पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। यह है मुद्दा। इसे ही लेकर तमिलनाडु में किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता अय्या कन्नू कर रहे हैं। इस समय प्रदर्शन तेज इसलिए हुआ है क्योंकि तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा वाले इलाके में कुरवाई फसल बोई गई है। यह धान की ही फसल होती है जिसकी बुवाई जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर में होती है। बुवाई के वक्त चाहिए होता है भरपूर पानी क्योंकि कर्नाटक ने तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी नहीं छोड़ा है। तो प्रदर्शन शुरू हो गया है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कन्नू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने और राज्य के किसानों के लिए ?1 लाख करोड़ के मुआवजे की मांग करने की अपील की है। कन्नू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को हर महीने तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। अब तक कर्नाटक के पास 80 टीएमसी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा पानी है। कर्नाटक के सीएम डी के शिव कुमार ने तमिलनाडु के लिए 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने से इंकार कर दिया। अगर वे पानी नहीं छोड़ते हैं तो वे कर्नाटक में नुकसान करेंगे और वे अपने लोगों और राज्य को बचाने के लिए 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं। हमारे सीएम जोसेफ विजय को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करके कर्नाटक से ?1 लाख करोड़ की मुआवजे की मांग करनी चाहिए। प्रोटेस्ट के निशाने पर कर्नाटक सरकार के साथ-साथ तमिलनाडु की विजय सरकार भी है। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन पहुंच गए थपुर जहां प्रोटेस्ट जारी था। प्रोटेस्ट के दौरान उदयनिधि स्पीच देना शुरू करते हैं।

लगातार सरकार और सीएम विजय पर निशाना साधते हैं। जब उदयनिधि बोल रहे थे तब मंच के सामने मौजूद लोग एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन का नाम चिल्लाने लगते हैं। उदयनिधि चुप हो जाते हैं। फिर पानी के ही रेफरेंस से एक आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। मंच पर मौजूद और सामने खड़े लोग हंसने लगते हैं। फिर उदयनिधि एक पॉज लेते हुए कहते हैं, मैं कावेरी नदी के पानी की बात कर रहा हूं। जिसने इस बात पर मुहर ही लगा दी कि उदयनिधि के बयान को जिस तरह से समझा जा रहा है, वह असल में वही कहना भी चाह रहे थे। बयान आया तो विवाद शुरू हुआ। विजय की पार्टी टीवी ने उदयनिधि को निशाने पर ले लिया। पूर्व बीजेपी नेता के अन्नामलई ने भी इस बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा जब मैं कल वैगई नदी की सफाई कर रहा था तो मैंने सोचा क्या इससे भी बुरा प्रदूषण कहीं हो सकता है। फिर मैंने उदयनिधि स्टालिन का भाषण सुना। उदयनिधि के बयान के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक थवरुर ईस्ट पुलिस ने बीएएनएस की धारा 196, 192, 352, 79, 296 बी 61, 3512 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद 4 अगस्त को तमिलनाडु पुलिस की एक टीम उदयनिधि के आवास पर पहुंच गई। पहले उनकी लीगल टीम और पुलिस के बीच बातचीत होती रही। कारवाई टालने की कोशिश हुई। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उदयनिधि को हिरासत में ले लिया।

दरअसल जब तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी तो उदयनिधि स्टालिन कुछ भी बोलकर निकल जाते थे। कभी सनातन को डेंगू-मलेरिया कहा और इसका खात्मा करने की बात की, तो कभी हिन्दी भाषा को लेकर विवादित बयान दिया। अपनी सरकारी मशीनरी और कानूनी पेचिदगियों का इस्तेमाल कर वे हर बार निकल जाते थे। लेकिन इस बार मामला उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के खिलाफ निजी टिप्पणी का था। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की जुबान एक बार फिर बिगड़ी और इस बार नतीजा पहले से कहीं ज्यादा कठोर निकला. चेन्नई स्थित उनके घर से पुलिस ने उन्हें उठा लिया। पूर्व सीएम के बेटे उदयनिधि को पहली बार सवा शेर मिला। सीएम विजय ने इस पर तत्काल कार्रवाई की और 24 घंटे से कम समय में भी एक्शन लिया। उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि बड़बोले बयानों का जवाब अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। यह घटना सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। विजय की सरकार ने साफ दिखाया कि विपक्ष के नेता होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत टिप्पणियों और अभद्र बयानों से ऊपर नहीं है।

संसद का गतिरोध टूटे : असहमति के बावजूद, सहमति का रास्ता खोजें

ज्योति भास्कर

संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां सरकार और विपक्ष के बीच मतभेदों का समाधान संवाद और सांविधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन, मानसून सत्र में जिस तरह से लगातार गतिरोध बना हुआ है और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच बातचीत के किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचने के चलते दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, तो यह न केवल सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ती दूरी का संकेत है, बल्कि संसदीय कार्यप्रणाली के लिए भी चिंताजनक है।

उल्लेखनीय है कि विपक्ष चाहता है कि संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई पर सदन में चर्चा हो और गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर जवाब दें। इसके अतिरिक्त, कथित राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर भी चर्चा के लिए विपक्ष अड़ा है। इस बीच विपक्ष ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), महिला आरक्षण और परिसीमन संबंधी विधेयकों पर सर्वदलीय बैठक की भी मांग की है। लेकिन, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या किसी विषय पर चर्चा की मांग को संसद की पूरी कार्यवाही रोकने की शर्त से जोड़ना उचित संसदीय परंपरा है?

सरकार को घेरने के लिए कई अन्य लोकतांत्रिक माध्यम भी उपलब्ध हैं। संसद की कार्यवाही रोकना अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। सदन का सुचारु संचालन सरकार और विपक्ष, दोनों के कंधों पर होता है, ऐसे में, दोनों पक्षों की यह जिम्मेदारी भी है कि वे असहमति को सदन के कामकाज में बाधा का स्थायी कारण न बनने दें। संसद का समय केवल सांसदों का नहीं, बल्कि देश के करदाताओं और नागरिकों का भी है।

हर मिनट की कार्यवाही के पीछे सार्वजनिक धन खर्च होता है और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद की निष्क्रियता के कारण अनेक विधायी और जनहित के मुद्दे लंबित रह जाते हैं। लगातार व्यवधान की संस्कृति अंततः सरकार से ज्यादा लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाती है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को खत्म हो रहा है। लिहाजा, अगला हफ्ता बेहद अहम होने वाला है। अगर यह सत्र इसी तरह शोर-शराबे और हंगामे के बीच समाप्त होता है, तो यह सरकार और विपक्ष, दोनों की विफलता होगी।

इसलिए, अब भी समय है कि दोनों पक्ष राजनीतिक जिद से ऊपर उठते हुए टकराव के बजाय संवाद को प्राथमिकता दें। संसद चलेगी, तभी सरकार से सवाल होंगे, विपक्ष अपनी बात रख सकेगा और जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक निर्णय हो सकेंगे। लोकतंत्र में जीत केवल विधेयक पारित कराने में नहीं, बल्कि असहमति के बावजूद, सहमति का रास्ता खोजने में होती है।

एमपी में कुशवाहा वोट बैंक की ताकत के आगे झुकी भाजपा

नीरज कुमार दुबे

मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा राजनीतिक संदेश दिया है, जिसकी गूंज अब पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर के एक विवादित बयान से शुरू हुआ विवाद आखिरकार सार्वजनिक माफी तक पहुंच गया। भाजपा की आंतरिक समीक्षा में यह संकेत मिलने के बाद कि कुशवाहा समाज की नाराजगी पार्टी की हार का बड़ा कारण बनी, तोमर ने स्वयं आगे आकर अपने शब्द वापस लिए और कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी इस समाज का अपमान करने की नहीं सोचा।

पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब 31 जुलाई को मुरैना में भाजपा के जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा के निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशवाहा समाज को संबोधित करते हुए कहा कि यह समाज बीच-बीच में गुलाटी खाता रहा और इसी कारण उसने अपनी विश्वसनीयता को खंडित किया। उन्होंने यह भी कहा कि एक समय ऐसा था जब कुशवाहा समाज भाजपा का मजबूत समर्थक माना जाता था और भाजपा ने उस दौर में भी समाज को सम्मान दिया, जब अन्य राजनीतिक दल उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने पूर्व नेता कालीचरण कुशवाहा को टिकट दिए जाने का उदाहरण भी प्रस्तुत किया।

हालांकि, कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक भूचाल आ गया। कुशवाहा समाज के विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों ने इस टिप्पणी को पूरे समाज की राजनीतिक निष्ठा

पर सवाल बताकर तीखी आपत्ति जताई। कांग्रेस ने भी इसे तुरंत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का अपमान बताते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती और उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर से सार्वजनिक माफी की मांग की।

इस बीच, दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने भाजपा की मुश्किलें और बढ़ा दीं। कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने भाजपा प्रत्याशी आशीष तिवारी को 6,016 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। भाजपा की आंतरिक समीक्षा में यह बात सामने आई कि दतिया के लगभग 12 प्रतिशत मतदाता रहे कुशवाहा समाज का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की ओर खिसक गया, जिसने चुनावी परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। इसके बाद भाजपा संगठन ने हार की व्यापक समीक्षा शुरू की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ नेताओं और चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक की, दतिया जिला इकाई को भंग किया गया, समीक्षा समितियां गठित की गईं और संगठनात्मक कमजोरियों के साथ-साथ संभावित अंदरूनी असंतोष की भी जांच शुरू हुई।

इसी राजनीतिक आत्ममंथन के बीच नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशवाहा समाज के नाम हस्ताक्षरित पत्र जारी कर अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि कमलेश कुशवाहा के घर आयोजित कार्यक्रम पारिवारिक वातावरण में था और उसी संदर्भ में बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि उनका और कुशवाहा समाज का रिश्ता परस्पर पूरक है तथा उन्होंने जीवनभर इस समाज का सम्मान किया है और आगे भी करते रहेंगे। यदि उनके शब्दों से किसी की भावना आहत हुई है तो वह अपने शब्द वापस लेते हैं और इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। उनका यह बयान भाजपा के भीतर बढ़ी राजनीतिक बेचैनी और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

दरअसल, यह पूरा घटनाक्रम केवल एक बयान और माफी तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की बदलती सामाजिक-राजनीतिक राजनीति का संकेत भी देता है। राज्य की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग आधी हिस्सेदारी रखता है और कुशवाहा समाज इस वर्ग का एक प्रभावशाली हिस्सा माना जाता है। ग्वालियर-चंबल अंचल के मुरैना, दतिया, भिंड और ग्वालियर जैसे जिलों से लेकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र तक इस समाज की उल्लेखनीय उपस्थिति है। कई विधानसभा सीटों पर यह समाज जीत-हार तय करने की क्षमता रखता है।

विशेष रूप से दतिया जैसी सीट पर, जहां कुशवाहा मतदाता लगभग 12 प्रतिशत हैं, किसी भी दल के लिए इस समाज की अनदेखी राजनीतिक जोखिम बन सकती है। यही कारण है कि भाजपा ने पिछले दो दशकों में ओबीसी सामाजिक समीकरणों के केंद्र में कुशवाहा समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया। दूसरी ओर कांग्रेस भी अब इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। पार्टी ने सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के नेतृत्व में बूथ स्तर तक व्यापक अभियान चलाया, जिसका असर दतिया उपचुनाव में दिखाई दिया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश में केवल एक बड़ा वोट बैंक नहीं, बल्कि एक प्रभावी स्विंग फैक्टर भी है। यदि समाज को सम्मान, पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी का संदेश मिलता है तो वह किसी भी दल के साथ मजबूती से खड़ा हो सकता है। लेकिन उपेक्षा या अपमान की भावना पैदा होने पर उसका रुख तेजी से बदलने की क्षमता भी रखता है। यही वजह है कि नरेंद्र सिंह तोमर के गुलाटी वाले बयान के बाद भाजपा को सार्वजनिक रूप से डैमेज कंट्रोल करना पड़ा।

बहरहाल, दतिया उपचुनाव ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मध्य प्रदेश की आगामी राजनीतिक लड़ाई केवल नेताओं के भाषणों या चुनावी नारों से नहीं जीती जाएगी। सामाजिक सम्मान, प्रतिनिधित्व और ओबीसी वर्गों के साथ मजबूत संवाद आने वाले चुनावों की दिशा तय करेगा। नरेंद्र सिंह तोमर की सार्वजनिक माफी इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कुशवाहा समाज अब केवल एक वोट बैंक नहीं, बल्कि सत्ता का समीकरण बदलने वाली निर्णायक राजनीतिक ताकत बन चुका है।

संसदीय-गतिरोध से नहीं चलेगा लोकतंत्र, संवाद ही है समाधान

ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संसद है। यही वह सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है जहां राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य से जुड़े विषयों पर गंभीर विमर्श होता है, सरकार जवाबदेह बनती है, विपक्ष जनभावनाओं को स्वर देता है और कानूनों के माध्यम से देश के विकास की दिशा तय होती है। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज संसद संवाद और सहमति का मंच बनने के बजाय टकराव, आरोप-प्रत्यारोप, नारेबाजी और राजनीतिक हठधर्मिता का अखाड़ा बनती जा रही है। मानसून सत्र में जिस प्रकार लगातार गतिरोध बना हुआ है, उससे केवल संसदीय कार्यवाही ही बाधित नहीं हो रही, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा भी आहत हो रही है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए हुई बातचीत भी किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। यह स्थिति बताती है कि दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक आग्रहों में इतने उलझ गए हैं कि राष्ट्रहित पीछे छूट गया है। विपक्ष की ओर से यह शर्त रखी जा रही है कि जब तक कुछ विशेष मुद्दों पर सरकार सदन में बयान और चर्चा के लिए तैयार नहीं होती, तब तक संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। दूसरी ओर सरकार भी अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर अडिग है। परिणाम यह है कि संसद का बहुमूल्य समय निरर्थक विवादों की भेंट चढ़ रहा है।

लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, किंतु असहमति को अराजकता में बदल देना लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी है। सरकार को कठघरे में खड़ा करना विपक्ष का अधिकार है, परंतु संसद को ठप कर देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में विरोध की भी मर्यादा होती है। जब विरोध संसद को चलने ही न दे, तब वह लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक दायित्वों की उपेक्षा बन जाता है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंताजनक प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है कि संसद सत्र प्रारंभ होने से पहले ऐसे मुद्दे राजनीतिक रूप से उछाले जाते हैं, जिनके आधार पर पूरे सत्र को बाधित किया जा सके। परिणामस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के पारित हो जाते हैं अथवा कई विधेयक लंबित रह जाते हैं। इससे सबसे अधिक नुकसान देश को

होता है। संसद का प्रत्येक मिनट करोड़ों रुपये की सार्वजनिक धनराशि से संचालित होता है। यदि वह समय केवल शोर-शराबे और नारेबाजी में बीत जाए तो यह करदाताओं के धन और लोकतांत्रिक विश्वास-दोनों का अपमान है।

लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम है। महात्मा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक भारतीय राजनीति की श्रेष्ठ परंपरा संवाद, सहमति और संवेदनशीलता की रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने दुराग्रह छोड़कर संवाद की मेज पर बैठें। संसद की गरिमा इस बात में नहीं कि कौन किसे अधिक कठघरे में खड़ा करता है, बल्कि इस बात में है कि राष्ट्रहित के प्रश्नों पर कितनी गंभीरता से विचार किया जाता है। विशेष रूप से कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल आंदोलन और विरोध का नाम नहीं है। विपक्ष की भूमिका सरकार को गिराने की नहीं, बल्कि लोकतंत्र को संभालने की होती है। यदि प्रत्येक मुद्दे पर संसद को बाधित करने की रणनीति अपनाई जाएगी तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि विपक्ष के पास वैकल्पिक नीति और दृष्टि का अभाव है। लोकतंत्र में जनता केवल विरोध नहीं, समाधान भी चाहती है। यदि विपक्ष स्वयं संवाद से दूरी बनाएगा तो 'संवाद से समाधान' का आदर्श केवल नारा बनकर रह जाएगा।

सरकार की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत का अर्थ मनमानी नहीं होता। सरकार को भी विपक्ष की उचित मांगों को सुनना चाहिए और जहां संभव हो, सहमति का मार्ग निकालना चाहिए। संसद किसी एक दल की नहीं, पूरे राष्ट्र की संस्था है। इसलिए सरकार को भी संवेदनशीलता, धैर्य और व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देना होगा। किंतु यदि संवाद का प्रत्येक प्रयास केवल राजनीतिक शर्तों और हठधर्मिता में उलझ जाए तो समाधान की संभावनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता राजनीतिक परिपक्वता की है। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हर मुद्दे को चुनावी लाभ-हानि के चश्मे से देखा जा रहा है। संसद में बहस कम और राजनीतिक संदेश अधिक दिए जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को कमजोर करती है। संसद का उद्देश्य जनकल्याणकारी नीतियों पर विचार करना है, न कि चुनावी रणनीतियों का मंच बन जाना।

देश आज आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, रोजगार, शिक्षा, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक समरसता जैसी अनेक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय संसद का प्रत्येक दिन अत्यंत मूल्यवान है। यदि यह समय केवल राजनीतिक टकराव में व्यतीत होगा तो विकास की गति अवश्य प्रभावित होगी। कानूनों में विलंब, नीतिगत निर्णयों की देरी और संसदीय अस्थिरता का सीधा प्रभाव आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती इस बात में नहीं कि संसद में कितना शोर हुआ, बल्कि इस बात में है कि वहां कितने सार्थक विचार सामने आए। स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष प्रतिद्वंद्वी अवश्य होते हैं, किंतु शत्रु नहीं। दोनों का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रहित होना चाहिए। यदि राजनीतिक दल इस मूल भावना को भूल जाएंगे तो लोकतंत्र केवल संख्या का खेल बनकर रह जाएगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल आत्ममंथन करें। विपक्ष अपने विरोध को रचनात्मक बनाए, सरकार अपने संवाद को व्यापक बनाए और दोनों मिलकर संसद की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करें। लोकतंत्र का भविष्य टकराव में नहीं, संवाद में सुरक्षित है। संसद की गरिमा नारेबाजी से नहीं, विचार-विमर्श से बढ़ती है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यदि संसद ही गतिरोध का प्रतीक बन जाएगी तो जनता का विश्वास कमजोर होगा, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। समय की पुकार है कि राजनीति चुनावों की सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रनिर्माण की दिशा में आगे बढ़े। पक्ष और विपक्ष दोनों यह स्मरण रखें कि वे किसी दल के नहीं, पहले भारत के प्रतिनिधि हैं। संसद की प्रत्येक घड़ी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। उसे हठ, अहंकार और राजनीतिक स्वार्थ की भेंट चढ़ाना भविष्य की पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा।

सुविधा की राजनीति और शिक्षा-जगत की दुविधा

गिरीश्वर मिश्र

लोकतंत्र के आधुनिक परिवेश में सामाजिक-राजनीतिक जीवन में उथल-पुथल एक आम बात है। विकसित और विकासशील सभी तरह के देशों में, जहां लोकतांत्रिक सरकारें सत्ता की बागडोर संभाल रही हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल है, वहां तमाम चीजों को लेकर बहसें होती रहती हैं। ऐसे में विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों की अलग-अलग राय भी होती है। यह स्थिति बहुत हद तक एक स्वस्थ राजनीतिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। सच कहें तो असहमति को आदर देना सभ्य समाज की वैचारिक परिपक्वता का ही परिचायक होता है। भारत जैसे देश में जहां राजनीतिक दलों की संख्या राष्ट्रीय स्तर की छह और क्षेत्रीय स्तर की साठ है, वैचारिक मतभेद होना सहज और स्वाभाविक है। ऊपर से क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक तथा आर्थिक विविधताएं भी बहुत तरह की हैं। ऐसी बहुलताओं वाले देश में किसी प्रश्न पर भिन्न प्रकार के विचारों को राजनैतिक विमर्श में सहनशीलता के साथ सम्मानजनक जगह मिलनी चाहिए। अक्सर विरोध की गुंजाइश न होने पर लोकतांत्रिक संस्थाएं और उनकी गतिविधियां पटरी से उतर कर ठप पड़ जाती हैं। गौरतलब है कि संविधान-सभा की बहसों और उसके बाद देश के संसदीय इतिहास में भी अनेक अवसरों पर संसद में तीखी बहसें होती रही हैं। कई सांसदों के वक्तव्यों में ज्ञान-विज्ञान और संस्कृति-सभ्यता की बातें भी हुआ करती थीं और हास्य-विनोद का पुट भी रहता था। इनसे लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिलता था। कुछ समय से इस तरह की परंपरा से अलग हट कर संसद में चल रही गतिविधि देखते-सुनते हुए आमजन हतप्रभ हैं और उनकी चिंता बढ़ती रही है। अब संसद-परिसर का वातावरण गंभीर विचार-विनिमय की जगह नाटकीय अभिनय के प्रदर्शन का मंच सा होता जा रहा है। संसद के भीतर और बाहर बार-बार मान्यवरों की ओर से ऐसा होना आम जन

को निराश करने वाला है। परीक्षा के पेपर बार-बार लीक होना शर्मनाक है और अब सरकार उसका संज्ञान लेकर सख्त कदम उठा रही है। परंतु शिक्षा के सवाल केवल परीक्षा तक ही सीमित नहीं हैं। राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश आदि कई राज्यों में सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत बता रही है कि शिक्षा की आधारशिला कमजोर हो रही है। वर्तमान सरकार ने शिक्षा में रुचि ली और उत्साहपूर्वक 2020 में एक नई शिक्षा नीति का ऐलान किया। तब से उस पर अमल चल रहा है, पर किसी भी बदलाव की तरह यह भी पेचीदा है। बड़े परिवर्तन के लिए अपेक्षित संसाधन और जरूरी तैयारी भी चाहिए। इस महत्वाकांक्षी बदलाव ने शिक्षा-जगत के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं। आज तक राष्ट्रीय बजट का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्चने का वादा पूरा नहीं हो सका है जबकि जनसंख्या में वृद्धि के हिसाब से शिक्षा के लिए इससे भी ज्यादा संसाधन आवंटित होना चाहिए। इस बीच संख्या की दृष्टि से शिक्षा-संस्थानों में इजाफा तो जरूर हुआ परंतु गुणवत्ता की दृष्टि से स्थिति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती। ऐसे में जरूरी है कि शिक्षा के प्रश्नों पर समग्रता में विचार किया जाए। देश की जनसंख्या में 65 प्रतिशत बच्चों, किशोरों और युवाओं की उपस्थिति है। इसलिए यथार्थ के धरातल पर आवश्यकता का आकलन कर संसाधनों, परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों के बीच तालमेल बैठाना जरूरी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही सामाजिक-आर्थिक उन्नति की यात्रा हो सकेगी।

रोज करें इन नामों का पाठ तो बुद्धि, समृद्धि आपके घर में रहेंगी

जब जब पृथ्वी पर दैत्यों के आतंक का साया रहा तब तब भगवान विष्णु, शिव, माता पार्वती यहां अवतरित हुए। भगवान गणेश भी चारों युगों में अवतरित हुए हैं। सतयुग में गणेश जी महोत्कट विनायक के नाम से, त्रेतायुग में मयूरेश्वर, द्वापर युग में शिवपुत्र गजानन के नाम से अवतरित हुए। और इस तरह पृथ्वी के अंत में जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे उसी दौरान भगवान गणेश धूम्रकेतु रूप में अवतरित होंगे। इस बात का उल्लेख हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है।

ये हैं गणेश परिवार भगवान गणेश के पिता भोलेनाथ हैं। मां पार्वती उनकी मां है। भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय उनके भाई हैं, और गजानन की बहन अशोक सुंदरी हैं। भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि। हालांकि दक्षिण भारत में गणेश जी को ब्रहमचारी के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी के दो पुत्र हैं शुभ और लाभ। उन्हें मोदक प्रिय है। लाल रंग के फूल से गणेशजी जल्द प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा उन्हें दुर्वा, शमी पत्र भी अर्पित करना चाहिए। गणेश जी के अस्त्र पाश और अंकुश हैं। और वाहन मूषक।

बुद्धि के लिए रोज करें इन नामों का पाठ हिंदू पौराणिक ग्रंथो में उल्लेखित है। यदि भगवान गणेश के इन बारह नामों का रोज पाठ करें तो बुद्धि, गृहक्लेश और समृद्धि आपके घर में रहेंगी। यह नाम क्रमशः सुमुख, एकदन्त, कपिल, गजकर्णक, लम्बोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचन्द्र, विघ्नराज, द्वैमातुर, गणाधिप, हेरम्ब, गजानन।

कृष्ण का आभामंडल नीला क्यों।

कृष्ण की हर छवि में एक नीलिमा जरूर दिखाई जाती है। एक व्यक्ति या एक व्यक्तित्व के रूप में उनके साथ आखिर क्यों जुडा है यह रंग क्या है इस रंग की खासियत आइए जानते हैं-

नीला रंग विस्तार को दर्शाता है। आप देखेंगे कि इस जगत में जो कोई भी चीज बेहद विशाल और आपकी समझ से परे है, उसका रंग आमतौर पर नीला है, चाहे वह आकाश हो या समुंदर। जो कुछ भी आपकी समझ से बडा है, वह नीला होगा, क्योंकि नीला रंग सब को शामिल करने का आधार है। आपको पता ही है कि कृष्ण के शरीर का रंग नीला माना जाता है। इस नीलेपन का मतलब जरूरी नहीं है कि उनकी त्वचा का रंग नीला था। हो सकता है, वे श्याम रंग के हों, लेकिन जो लोग जागरूक थे, उन्होंने उनकी ऊर्जा के नीलेपन को देखा और उनका वर्णन नीले वर्ण वाले के तौर पर किया। आमतौर पर देखें तो पुरुष का स्वभाव ही ऐसा होता है कि अगर उसमें प्रेम का अहसास जागने लगे तो वह बेवकूफियों से भरी मजेदार हरकतें करने लगता है। जबकि किसी स्त्री के साथ अगर ऐसा हो तो वह और भी सुंदर लगने लगती है। कृष्ण की पकृति के बारे में की गई सभी व्याख्याओं में नीला रंग आम है, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना उनका एक ऐसा गुण था, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वह कौन थे, वह क्या थे, इस बात को लेकर तमाम विवाद हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनका स्वभाव सभी को साथ लेकर चलने वाला था। चूंकि श्रीकृष्ण की ऊर्जा या यूं कहिए कि उनके प्रभामंडल का सबसे बाहरी घेरा नीला था, इसीलिए उनमें गजब का आकर्षण था। उनके आकर्षक होने की वजह उनकी नाक का सुडौल होना या उनकी आंखों की खूबसूरती नहीं थी। दुनिया में अच्छी नाक, सुंदर आंखों वाले और खूबसूरत कद-काठी के कितने ही लोग हैं, लेकिन उन सभी में उतना आकर्षण नहीं होता। यह किसी व्यक्ति विशेष के प्रभामंडल की नीलिमा है, जो अचानक उसे जबर्दस्त तरीके से आकर्षक बना देती है। लोग कहते हैं कि कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से नीले थे, लेकिन यह तीन हजार साल पुरानी जनश्रुति है।

उनकी नीलिमा या सबको सम्मोहित करने की उनकी क्षमता कुछ ऐसी थी कि जो लोग उनके कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, अनजाने में ही सही, लेकिन वे भी उनके सामने हार मान लेते थे। नीला रंग विस्तार को दर्शाता है। आप देखेंगे कि इस जगत में जो कोई भी चीज बेहद विशाल और आपकी समझ से परे है, उसका रंग आमतौर पर नीला है, चाहे वह आकाश हो या समुंदर वे उन लोगों को भी आसानी से अपनी तरफ कर लेते थे, जो उन्हें बुरा कहते थे और न जाने कितनी ही बार उन्हें मारने की कोशिश कर चुके थे। हालांकि उनके और भी कई पहलू थे, लेकिन उनकी व्यक्तित्व की यह नीलिमा लगातार उनके हर काम में मदद करती थी। इसी वजह से वे बेहद सम्मोहक बन गए थे। चाहे आदमी हो या औरत, हर कोई शर्मो-हया छोड कर उनके प्रेम में पागल हो जाता था। लोग उन पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाते थे। महिलाएं तो एक कदम और आगे थीं। पुरुषों के साथ यह दुर्भाग्य रहा है कि वे अपने प्रेम को आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते।

केवल एक शब्द कहने में ही आदमी की सारी उम्र निकल जाती है, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं थे। वह पूरी आजादी से खुद को व्यक्त करते थे। वैसे मुझे भी ऐसा करने में कोई समस्या नहीं होती। आमतौर पर देखें तो पुरुष का स्वभाव ही ऐसा होता है कि अगर उसमें प्रेम का अहसास जागने लगे तो वह बेवकूफियों से भरी मजेदार हरकतें करने लगता है। जबकि किसी स्त्री के साथ अगर ऐसा हो तो वह और भी सुंदर लगने लगती है। पुरुष प्रेम में खुद को अजीब और असहज महसूस करने लगता है। वह प्रेम नहीं चाहता, बस प्रेम-क्रीडा करना चाहता है।

भगवान गणेश को क्यों नहीं चढाई जाती है तुलसी

तुलसी को बेसिल पौधे के नाम से भी जाना जाता है और यह हिन्दुओं के लिए काफी पावन पेड है। यह महाविष्णु भगवान की पूजा के लिए व्यापक रूप से इस्तमाल किया जाता है। तुलसी में कई औषधीय गुण भी होते हैं। तुलसी के पौधे को मृत इंसान के मुंह में इस विश्वास के साथ रखा जाता है कि इससे वह इंसान को वैकुण्ठ या भगवान विष्णु के निवास स्थान पर पहुँच जाएगा। हालांकि, तुलसी को भगवान गणेश पर नहीं चढाया जाता है और इसके पीछे पुराण से सम्बंधित एक कहानी भी है। भगवान गणेश की कृपा चाहिये तो चढाइये उनके पसंदीदा फूल तुलसी एक समय एक लडकी हुआ करती थी जो भगवान महाविष्णु की भक्त थी। वह भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहती थी और एक दिन उन्हें गणेश मिले जो एक सुन्दर बगिया में खुशबूदार पेडों के पास ध्यान में मग्न थे। गणेश ने चमकीला पीला वस्त्र पहना था और उनके पूरे शरीर पर चन्दन का लेप लगा था। गणेश के इस रूप को देखकर तुलसी मोहित हो गयी और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया।

भगवान गणेश ने कहा कि वह ब्रमहचर्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं वह सन्यासी हैं और शादी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते क्यूंकि इससे उनके संयमी जीवन पर असर पडेगा। तुलसी यह सुनकर गुस्सा हुई और गणेश के इस वक्तव्य पर क्षुब्ध होकर उन्होंने

गणेश को शाप दिया कि उनकी इच्छा के बिना भी उनको शादी करनी पडेगी। भले ही गणेश अत्यंत परोपकारी थे पर तुलसी के इस आचरण से उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने तुलसी को श्राप दिया कि उसकी शादी एक दानव से होगी और उसे काफी कष्ट भुगतना पडेगा। तुलसी को अपनी गलती का अंदाजा हो गया और उसने भगवान गणेश से विनती की ताकि वह उसे इस कठोर श्राप से मुक्त कर दें।

भगवान गणेश खुश हुए और उसे माफकर दिया। उन्होंने कहा कि श्राप के अनुसार उसकी शादी एक दानव से होगी पर एक जीवन के बाद अगले जीवन में वह पेड बन जायेगी। उसके बाद सब में वह अपने अद्भुत औषधीय गुण के कारण जानी जायेगी और भगवान महाविष्णु की प्रिय होगी। महाविष्णु तुलसी चढाये जाने से काफी खुश होंगे और इस तरह उसकी एक उन्नत जगह होगी। गणेश का श्राप और आशीर्वाद दोनों ही सच हुए और तुलसी का विवाह शंकचूड नाम के दानव से हुआ। उसने पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारी और फिर उसके बाद अगले सारे जन्म में तुसली के पेड का रूप लिया।

गणेश के विश्वास के अनुसार महाविष्णु भगवान की पूजा के लिए यह एक उत्तम पौधे के रूप में इस्तमाल होने लगा। तुलसी के चढावे के बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा अधूरी रहने लगी। यह कारण है कि भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढाया जाता है। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि कैसे तुलसी को यह पवित्र स्थान मिला। पुराणों के कहानियों से पता चलता है कि भगवान बुरे लोगों के साथ भी काफी दयालु थे। जब भी देवों द्वारा किसी दानव का वध होता था तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। इस तरह इस कहानी में गणेश की दया और कृपा का बखान है। इस कहानी को तब बताया गया जब लोगों ने पूछा कि भगवान गणेश को तुलसी क्यों नहीं चढाया जाता है। पुराने समय से तुलसी का इस्तमाल गणेश भगवान की पूजा में नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश को अर्का घास बहुत पसंद है।

क्या है हिंदू देवियों का रहस्य

सरस्वती-हिंदू धर्म की प्रमुख त्रिदेवियों में से एक माता सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है। हंस पर विराजमान मां सरस्वती ने धवल वस्त्र धारण किए हैं। सरस्वती के हाथ वीणा के वरदंड से शोभित हैं। संगीत, कला, शिक्षा और ज्ञान की देवी हैं सरस्वती। सरस्वती के नाम पर ही एक नदी का नाम सरस्वती था, जो प्राचीनकाल में शिवालिक की पहाडियों से निकलकर हरियाणा और राजस्थान में बहती थी और सिंधु खाडी में समाहित हो जाती थी।

माता लक्ष्मी - भगवान विष्णु की पत्नी और ऋषि भृगु की पुत्री देवी लक्ष्मी त्रिदेवियों में से एक हैं, जो धन और समृद्धि को देने वाली मानी गई हैं। लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू है और वह लक्ष्मी क्षीरसागर में भगवान विष्णु के साथ कमल पर वास करती हैं। लक्ष्मीजी को 2 रूपों में पूजा जाता है, श्रीरूप और लक्ष्मी रूप। इनका विशेष दिन शुक्रवार को माना गया है। भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र कहे गए हैं जिसमें प्रमुख हैं, आनंद, कर्दम, श्रीद और चिक्लीत।

गायत्री- गायत्री नाम से ऋग्वेद में एक सबसे लंबा छंद है। गायत्री को आद्याशक्ति प्रकृति के 5 स्वरूपों में एक माना गया है।

यही वेद माता कहलाती हैं। किसी समय ये सविता देव की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई थीं इसलिए इनका नाम सावित्री पड गया। इनका विग्रह तपाए हुए स्वर्ण के समान है। वेदों में अदिति के अलावा सविता का भी कई जगहों पर उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार वज्रनाश नामक राक्षस का वध करने के पश्चात ब्रहमाजी ने संसार की भलाई के लिए पुष्कर में एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रहमाजी यज्ञ करने हेतु पुष्कर पहुंच गए, लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी समय पर नहीं पहुंच सकीं। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुंचने की वजह से उन्होंने एक कन्या गायत्री से विवाह कर यज्ञ शुरू किया। उसी दौरान देवी सावित्री वहां पहुंचीं और ब्रहमा के बगल में दूसरी कन्या को बैठा देख क्रोधित हो गईं।

उन्होंने ब्रहमाजी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी, तब सावित्री से सभी देवताओं ने विनती की कि अपना श्राप वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी।

श्रद्धा - श्रद्धा कर्दम ऋषि एवं देवहूति की तृतीय कन्या थी। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ था। अंगिरा और श्रद्धा से सिनीबाला, कुहु, राका एवं अनुमति नामक पुत्रियां तथा तथ्य और बृहस्पति नामक पुत्र हुए। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं।

शचि - शचि स्कंद पुराण के पुलोमा पुत्री शचि का भी वेदों में उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में दैत्यराज पुलोम की पुत्री शचि ने देवराज इंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ज्वालपाधाम में हिमालय की अधिष्ठात्री देवी पार्वती की तपस्या की थी। मां पार्वती ने शचि की तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे दीप्त ज्वालेश्वरी के रूप में दर्शन दिए और शचि की मनोकामना पूर्ण की। जहां मां ने दर्शन दिए थे वह स्थान उत्तराखंड के गढवाल क्षेत्र में है। यहां माता ज्वाला देवी का एक मंदिर है। देवी शचि को इंद्राणी कहा जाता है। इंद्राणी देवी शचि ने अपने पति इंद्र के हाथ में ब्राहमणों द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाया था। उन्होंने ऐसाइ सलिएकिया, क्योंकि उस समय देवासुरसंग्राम चल रहा था। रक्षासूत्र बांधकर जब इंद्र ने युद्ध किया तो वे विजयी हुए। कुछ लोगों का मानना है कि तभी से रक्षाबंधन का यह पर्व शुरू हुआ।

सावित्री - ब्रहमा की पत्नी का नाम सावित्री देवी है। ब्रहमा ने एक और स्त्री से विवाहकिया था जिसकानाम गायत्री है। सावित्रीकी एक पुत्री का नाम सरस्वती है।

शालीग्राम की कहानी: विष्णु को श्राप क्यों मिला

जालंधर: शिव का एक भाग एक समय जलंधर नाम कएक पराक्रमी असुर था। जो शिव की तीसरी आँख से उत्पन्न हुआ था। यही कारण था कि वह अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। इसका विवाह वृंदा नामक कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इसके पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर अजेय हो गया था। जालंधर और शिव का युद्ध इसने एक युद्ध में भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। अपने अजेय होने पर इसे अभिमान हो गया और स्वर्ग के देवताओं को परेशान करने लगा। दुःखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गये और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। क्योंकि जालंधर को तभी हराया जा सकता जब पत्नी वृंदा पवित्रता को भांग कर दिया जाए।

वृंदा: विष्णु की सबसे बडी भक्त एक असुर की बेटी और पत्नी होने के बावजूद वह भगवान विष्णु की भक्त थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उन पर उसे पूरा विश्वास करती थी। विष्णु का विश्वासघात सभी देवताओं ने देखा कि शिव भी उसे हरा नहीं पाये तो वे विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलांधर का रूप

धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गयी और वह युद्ध में मारा गया।

वृंदा का अभिशाप जब वृंदा ने भगवान विष्णु को छुआ तब उसे पता चला कि वह जालंधर नहीं है। और उसने पूछा कि वह कौन हैं। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे इसलिए वृंदा के शाप को जिवित रखने के लिए उन्होनें अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया जो शालिग्राम कहलाया।

तुलसी भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुमहारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा।

यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। शालीग्राम तुलसी का विवाह वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाये रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया।

इसी घटना को याद रखने के लिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है।

मन की स्वतंत्रता

यदि व्यक्ति को भिन्न होने की स्वतंत्रता दी जाए, तो कई जरूरी कार्य भी समय से पहले पूरे हो जाते हैं। ओशो का चिंतन एक दार्शनिक था। एक बार उसने एक किसान से पूछा, कोल्हू का बैल चल रहा है। तेल पेरा जा रहा है। बैल को न तो कोई हांकने वाला है और न ही कोल्हू को चलाने वाला। फिर यह आराम करने के लिए बैल रुक क्यों नहीं जाता। किसान ने कहा कि गौर से देखने पर जवाब मिल जाएगा।

दार्शनिक ने गौर से देखा कि बैलों की आंखों पर पट्टियां बंधी हैं जैसे तांगे में चलने वाले घोडे की आंखों पर पट्टियां बंधी होती हैं, ताकि उसे सिर्फसामने दिखाई दे। वह इधर-उधर न देख पाए। साथ ही गले में घंटियां बंधी हैं। घंटी की आवाज बंद होने के साथ ही उसे कोडे से फटकार लगा दी जाती है। साधारण आदमी भी कोल्हू का बैल है, चलता जाता है। उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी हैं! गले में घंटी बंधी है। घंटी बंद होते ही सबकी डांट-फटकार मिलने लगती है।

सुबह, दोपहर, सांझ, रात में वही सब काम करता जा रहा है, जो वह रोज करता है। वही क्रोध, वही काम, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार। सुख और दुख, दोनों पुराने हैं। हमारा मन स्वतंत्र नहीं है। दूसरों की इच्छाओं, आदेशों से ही हमें चलना है। अपनी मर्जी के काम करने या कपडे पहनने की भी स्वतंत्रता नहीं है। समाज ने हमारे लिए सभी इंतजाम कर दिए हैं। सभी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आजादी की बात की जाती है, लेकिन व्यक्ति चौबीसों घंटे गुलाम है। आजादी सिर्फएक थोथा शब्द है, जिसको हम दोहराते रहते हैं तोतों की तरह; और बहुत दिन दोहराने के कारण खुद ही भरोसा कर लेते हैं कि जरूर आजादी होगी, क्योंकि सभी लोग आजादी की बात कर रहे हैं।

आजादी कहां है। क्या हमने कभी भिन्न होने की चाहत की है। कभी भिन्न होने की चाह पैदा करें। कोई भी कलात्मक कार्य करें। आप देखेंगे कि कलात्मक कार्यों का प्रभाव सीधे मन पर होता है। मन आजाद होकर कमल के फूलों की तरह खिल जाता है। कई जरूरी काम पूर्ण हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर आजादी उस दिन होगी, जिस दिन हम व्यक्ति को भिन्न होने की स्वतंत्रता देंगे।

स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था

स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बुद्धिमान थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। जब भी वो किसी साथी से बात करते तो वह तल्लीनता से उनकी बातों को सुनते थे। एक बार ऐसी ही स्थिति में शिक्षक कक्षा में आ गए और पढाना शुरू कर दिया। छात्रों के पता ही नहीं चला। शिक्षक ने कहा, 'सभी छात्र वहां एक जगह क्यों एकत्र हैं।' शिक्षक वहां तुरंत पहुंचे और छात्रों से प्रश्न पूछने लगे। उनके प्रश्नों का उत्तर कोई छात्र नहीं दे सका। लेकिन नरेंद्र ने उस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे दिया। शिक्षक ने सभी छात्रों को खडे रहने की सजा दी। लेकिन नरेंद्र ने कहा कि मैं इन सभी छात्रों से बात कर रहा था तो इनका ध्यान वहां नहीं था। लेकिन में सुन रहा था।

संक्षेप में नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद बचपन से ही साहसी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया और जिदंगी भर ईमानदारी का पाठ पढाया।

अपना भविष्य जानने की उत्कंठा सभी के मन में रहती है

लोग यह जानते हैं कि आकाश में चमकने वाले सितारे नक्षत्र कहलाते हैं। अपनी-अपनी राशियां देखकर और ग्रहों के शुभाशुभत्व को ध्यान में रखकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भविष्य जानने की उत्कंठा सभी के मन में रहती है। ग्रह नौ और राशियां बारह सर्वविदित ही है। सामान्य अर्थ में नक्षत्र यानि तारे। यदि नक्षत्र का अर्थ और स्पष्ट किया जाये तो हम यह कह सकते हैं कि चंद्रमा के पथ में पडने वाले कुछ विशेष तारों के विभिन्न समूह जिनके नाम अलग-अलग हैं और जिनकी संख्या सत्ताइस है। चंद्रमा को नक्षत्रों का राजा यानि नक्षत्रराज कहा जाता है। गगन मंडल में ग्रहों की स्थिति का पता करने के लिये दैवज्ञों ने वृत्ताकार आकाश या भचक्र के 3600 अंशों को 12 समान खंडों में बांटा। तीस अंश के ये भाग राशि कहलाये। जिस भाग का जैसा स्वरूप दिखाई देता है उसी के आधार पर राशियों का नामकरण किया गया है । इन्हें यंत्रादि की सहायता से देखा जा सकता है। इन्हीं भागों के नीचे ग्रहों का चलना फिरना होता रहता है और तभी यह कहते हैं कि फलां-फलां ग्रह फलां-फलां राशि पर भ्रमण कर रहा है। इसका विचार फलादेश करते समय किया जाता है। ऐसे 27 चिह ढूढें गये जो न चलने फिरने के कारण नक्षत्र कहलाने लगे यानि न क्षरति इति नक्षत्रम''। भचक्र के 3600 अंशों को 27 से विभाजित करने पर 130 20' का क्षेत्र नक्षत्र कहलाया। ग्रह 9 होते हैं यह हम सभी जानते हैं। ज्योतिष में इन्हीं नवग्रहों का विचार किया जाता है। सात ग्रह सात दिनों के अधिपति हैं। शेष दो ग्रह राहु व केतु हैं। सूर्य को एक नक्षत्र को पार करने में करीब-करीब पंद्रह दिनों का समय लग जाता है जबकि चंद्रमा को ऐसा करने में करीब एक दिन का समय लगता है। इस तरह चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों को लगभग एक मास में पार कर लेता है ।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

योगी सरकार पर भड़कीं आनंदीबेन

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों की हालत देखकर नाराजगी जताई है. राज्यपाल ने हॉस्टल की मेस में बन रहे खाने की जांच की और खाना पकाने में इस्तेमाल हो रहे तेल की गुणवत्ता पर सीधा सवाल उठाया. उन्होंने मौके पर ही फूड सेफ्टी अधिकारियों को बुलाकर सैंपल लेने के निर्देश दिए. यह पूरा मामला यूनिवर्सिटी के 45वें दीक्षांत समारोह के दौरान सामने आया, जब राज्यपाल खुद गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रुकी हुई थीं.

राज्यपाल ने कहा कि यह गोरखपुर है, जहां खुद मुख्यमंत्री रहते हैं, अगर यहीं ऐसी कमियां रह जाएंगी तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा. उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में कुल 9 हॉस्टल हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं. इनमें से एक हॉस्टल की मरम्मत का काम चल रहा है क्योंकि इमारत जर्जर हालत में थी. वहीं 6 ब्वॉयज हॉस्टल में से 2 में मरम्मत का काम जारी है।

टीचरों ने ही लीक किया नीट पेपर

नईदिल्ली। नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है. जांच में पता चला है कि पेपर लीक की शुरुआत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के साथ काम कर रहे विषय विशेषज्ञों से हुई थी. इन विशेषज्ञों ने अपनी अधिकृत पहुंच का गलत इस्तेमाल करके पेपर का कंटेंट बाहर निकाला. इसके बाद यह पेपर कई राज्यों से होते हुए जयपुर तक पहुंचा, जहां इसे छापकर बांटा गया. सीबीआई ने फोरेंसिक जांच, पैसों के लेनदेन के सबूत और नकदी बरामद करके इस पूरे नेटवर्क को उजागर किया है. इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे विशेषज्ञ शामिल थे. बॉटनी और जूलॉजी की जिम्मेदारी मनीषा गुरुनाथ मांधरे के पास थी, केमिस्ट्री की जिम्मेदारी प्रल्हाद विठ्ठलराव कुलकर्णी यानी पीवी कुलकर्णी के पास थी और फिजिक्स की जिम्मेदारी मनीषा संजय हवलदार के पास थी. अप्रैल 2026 में इन लोगों ने पूरे छपे हुए पेपर लीक करने के बजाय सवालों का कंटेंट निकालने का तरीका अपनाया. कुलकर्णी और मांधरे ने पुणे में अपने घरों पर गुपचुप तरीके से खास रिवीजन सेशन आयोजित किए।

आम लोगों से यूपीआई फीस नहीं लेंगे: निर्मला

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक, 2027 बीते मंगलवार को संसद में पेश किया है. इस बिल को लेकर लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है. इस बिल के तहत मर्चेंट डिस?काउंट रेट लागू करने की बात कही गई है. यह चार्ज 2000 रुपये से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लागू किया जा सकता है. यानी अगर 2000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट एकबार में किया जाता है, तो एमडीआर चार्ज देना होगा. संसद में विधेयक पेश होने के बाद से ही कन्फ्यूजन इस बात का है कि आखिर ये चार्ज किसपर लागू होगा. विपक्ष लगातार सरकार पर इसे लेकर निशाना साधता नजर आया. अब सरकार ने खुद साफ-साफ बता दिया है कि ये एमडीआर चार्ज किस पर लागू होगा. वित्त मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए तस्वीर साफ की है।

एफसीआरए बिल पर सुप्रिया सुले ने जताई आपत्ति

नईदिल्ली। शरद पवार की अगुवाई वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग को अपने आप शक की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि या तो इस बिल को वापस ले लिया जाए या फिर इसकी विस्तार से जांच-पड़ताल के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाए। सुले ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को प्रस्तावित कानून पर चर्चा करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि अगले हफ्ते संसद में इस बिल पर चर्चा हो सकती है और इसे पारित भी किया जा सकता है। शनिवार को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए सुले ने कहा कि उनकी पार्टी इस बिल के मौजूदा स्वरूप से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेना चाहती है, तो इस कानून को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

भावना बनीं पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर

नईदिल्ली. भारतीय वायुसेना में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है. स्क्वॉड्रन लीडर भावना कंठ ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है. वे पहली महिला फाइटर पायलट बन गईं जिन्होंने ग्वालियर स्थित टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी टैकडे में प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर यानी एफसीएल कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया. यह 20 सप्ताह का कोर्स भारतीय वायुसेना के सबसे कठिन और एडवांस लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक माना जाता है. इसे सिर्फ चुनिंदा फाइटर पायलटों के लिए आरक्षित रखा जाता है. इस कोर्स को पूरा करने के बाद पायलट जटिल हवाई लड़ाकू मिशनों का नेतृत्व करने योग्य हो जाते हैं. वायुसेना के अग्रिम लड़ाकू रणनीतिकारों में शामिल हो जाते हैं.टैकडे को भारतीय वायुसेना का टॉप गन स्कूल कहा जाता है. यहां पायलटों को एडवांस फाइटिंग स्ट्रैटेजी, मिशन प्लानिंग, हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले के ऑपरेशन तथा उच्च तीव्रता वाले परिचालन परिदृश्यों में नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' में राहुल गांधी ने बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं के मुद्दे उठाए

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार शाम कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में छात्रों से संवाद करते हुए बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य, पेपर लीक और छात्र आंदोलनों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने करीब 20 मिनट तक छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी की पुत्री मिराया भी मौजूद रहीं।

श्री गांधी ने मंच पर पहुंचते ही छात्रों से उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि युवाओं को आज सोशल मीडिया की रील देखने और बनाने में उलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा, आपसे कहा जाता है कि जितनी रील देखनी है और जितनी रील बनाना चाहते हो बनाओ। यह 21वीं सदी का नशा है।

उन्होंने कहा कि छात्र बीए, एमए, एलएलबी समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों में इस उम्मीद के साथ पढ़ाई करते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन देश में स्थायी रोजगार की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने दावा किया कि भारत में प्रत्येक एक हजार युवाओं में केवल 12 को ही स्थायी नौकरी मिलती है।

श्री गांधी ने आरोप लगाया कि युवाओं का डेटा कुछ लोगों द्वारा बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में करीब 40 करोड़ युवा हैं और यही देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। चीन की ताकत की चर्चा होती है, लेकिन भारत के युवाओं की क्षमता के सामने वह कुछ भी नहीं है।उन्होंने कहा कि परिवारों से शिक्षा पर लाखों करोड़ रुपये खर्च कराए जाते हैं और बदले में युवाओं को बीए-एमए जैसी डिग्रियां मिलती हैं, लेकिन डिग्री रोजगार की गारंटी नहीं देती। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान बिहार से आई एक छात्रा ने राहुल गांधी से संवाद करते हुए छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। छात्रा ने आरोप लगाया कि पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसने बताया कि 23 जुलाई को एक और प्रदर्शन की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई थी।छात्रा ने आरोप लगाया कि अगले दिन सिवान में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की घटना में एक छात्र की मौत हो गई। उसने कहा कि 25 जुलाई को जब छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे थे, उस दौरान बिहार में कई छात्र भयभीत थे और पुलिस द्वारा छात्रों को लाइब्रेरी से उठाए जाने की बात सामने आई।

एक अन्य छात्र ने मंच पर पहुंचकर राहुल गांधी को बताया कि 22 जुलाई को पटना में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने सिर और पैर पर लाठियां मारीं तथा आंसू गैस के गोले छोड़े। छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मियों की वर्दी पर पहचान संबंधी बैज नहीं थे और घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस तक नहीं आने दी गई। छात्र ने कहा कि उसे स्कूटी से अस्पताल ले जाना पड़ा और बाद में करीब 15 घंटे थाने में बैठाए रखा गया। उसने कहा कि छात्र पहले नौकरी के लिए आंदोलन करते हैं, फिर पेपर और उसके बाद परिणाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है। उसने सवाल किया कि हम छात्र हैं या आंदोलनजीवी हैं।छात्र ने कहा कि वह बिहार से आता है और वहां के छात्र सत्ता बदलने की ताकत रखते हैं।

प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले शाम छह बजे निर्धारित था, जिसे बाद में शाम सात बजे कर दिया गया। कार्यक्रम में प्रयागराज समेत 23 जिलों के छात्रों को बुलाया गया था। राहुल गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। भीड़ में शामिल कई छात्र ट्रकों और कंटेनरों पर चढ़कर कार्यक्रम को सुनते दिखाई दिए।

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सड़क पर भी युवाओं की भीड़ जमा हो गई। कई युवा हाथों में तिरंगा लेकर भी आगे बढ़ते दिखाई दिए।

कागज के टुकड़े जान नहीं बचाते...

पाकिस्तान-तुर्की डील के बाद सऊदी पर जमकर दहाड़ा ईरान ने

नईदिल्ली। 7 अगस्त की रात को दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींची गई है जिसने ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि भारत के रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इसे दुनिया के कई देश इस्लामिक नेटो की शुरुआत कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर और तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक साथ आने की खबर आई, ईरान ने ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरी दुनिया सहम गई। ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा कि सऊदी अरब सावधान रहे क्योंकि कागज के टुकड़े कभी भी जान नहीं बचाते। इस एग्रीमेंट की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज़ है। ठीक वैसे ही जैसे नाटो का आर्टिकल पांच कहता है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला हुआ तो बाकी सब मिलकर युद्ध लड़ेंगे। अब यही नियम पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की पर लागू होगा। अब आप सोचिए अगर कल को यमन की हूं विद्रोही या ईरान की सेना सऊदी अरब पर हमला करती है तो पाकिस्तान की फौज और तुर्की की वायु सेना को सऊदी के बचाव में सीधे युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा। यह वेस्ट एशिया के इतिहास में पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है।

सऊदी अरब ने आखिर तुर्की को क्यों चुना? : इसका जवाब है तुर्की के घातक बैरख्तर ड्रोंस। आज की तारीख में तुर्की दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ डिफेंस हब है। तुर्की के पास नेटो की ट्रेनिंग है और सीरिया लीबिया जैसे देशों में लड़ने का कड़वा अनुभव है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की माली हालत चाहे जो भी हो लेकिन उसके पास एक विशाल सेना और परमाणु हथियार है। सऊदी अरब को हमेशा से डर रहा है कि ईरान एक परमाणु शक्ति ना बन जाए। ऐसे में पाकिस्तान का परमाणु छाता सऊदी अरब को एक मानसिक सुरक्षा देता है। सऊदी अरब अपना पैसा लगाएगा। तुर्की अपनी टेक्नोलॉजी देगा और पाकिस्तान अपना सैन, मैन पावर और परमाणु ताकत। लेकिन इस पूरी कहानी में विलेन की एंट्री होती है ईरान के रूप में। ईरान के सांसद इब्राहिम रजई ने मक्का पैक को पेपर एग्रीमेंट कहकर इसकी धज्जियां उड़ा दी और खुद इस बात की पुष्टि की अपने एक्स अकाउंट पर की। ईरान का कहना है कि सऊदी अरब पहले अमेरिका के संरक्षण में था तब भी ईरान ने उसे नुकसान पहुंचाया।

ईरान का तर्क बड़ा सीधा है। क्या पाकिस्तान वाकई ईरान के खिलाफ परमाणु बम इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा? क्या तुर्की अपने आर्थिक हितों को दांव पर लगाकर ईरान से सीधी दुश्मनी लेगा? ईरान इसे सिर्फ एक दिखावा बता रहा है ताकि सऊदी अरब अपनी जनता को दिखा सके कि वो सुरक्षित है।

भारत के लिए स्थिति थोड़ी जटिल है। सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से सबसे अच्छे दौर में है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की का गठजोड़ हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या इंटरनेशनल फोरम। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अगर पाकिस्तान इस डिफेंस पैक के बहाने तुर्की के एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करता है और सऊदी के फंड से अपनी सैन्य मशीनरी को आधुनिक बनाता है तो ये भारत की सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन सकता है। हालांकि भारत को भरोसा है कि सऊदी अरब कभी भी भारत के हितों के खिलाफ इस पैक का इस्तेमाल नहीं होने देगा क्योंकि भारत सऊदी के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बाजार है।

खेल
प्रमुख समाचार

आशीष ने वर्ल्ड अंडर 20 में भारत को दिलाया रजत पदक

यूजीन। आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप में पुरूषों के भालाफेंक में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला जबकि राष्ट्रीय सीनियर रिकॉर्डधारी पूजा सिंह ने महिलाओं की ऊंची कूद के फाइनल में जगह बना ली। यादव ने तीसरे दौर में 74 . 09 मीटर का थ्रो फेंककर रजत पदक हासिल किया। वहीं भारत के टी धरणीधरन 72 . 35 मीटर के थ्रो के साथ छठे स्थान पर रहे।

यादव अपने सर्वश्रेष्ठ निजी प्रदर्शन से 40 सेमी पीछे रह गए। उन्होंने मार्च में पटियाला में इंडियन ओपन थ्रो प्रतिस्पर्धा में 74 . 49 मीटर का थ्रो फेंका था। 19 वर्ष के यादव दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के बाद इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए।

चोपड़ा ने 2016 में पोलैंड में 86 . 48 मीटर के विश्व जूनियर रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। यह रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है। दक्षिण अफ्रीका के जान हेंड्रिक हेमैंस ने 80 . 50 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता।

वहीं डोमिनिका के एडिसन जेम्स को कांस्य पदक मिला जिन्होंने 73 . 89 मीटर का थ्रो फेंका था। एक दिन पहले पुरूषों की 400 मीटर हीट के पहले दौर में अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले मोहम्मद अशफाक फाइनल में 46 . 20 सेकंड का समय निकालकर आठवें स्थान पर रहे। अमेरिका के जेडेन डेलोन ने 44 . 47 सेकंड के साथ स्वर्ण और उनके हमवतन किंसी विल्सन ने 44 . 62 मीटर के साथ रजत पदक जीता।

दक्षिण अफ्रीका के लीन्डर्ट के को कांस्य पदक मिला। महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा ने 1 . 79 मीटर के साथ फाइनल में जगह बनाई। दोनों क्वालीफिकेशन ग्रुप से 1 . 79 मीटर की बाधा पार करने वाले को फाइनल में जगह मिली। पुरूषों की लंबी कूद में शाहनवाज खान और जितिन अर्जुन ने फाइनल में जगह बना ली।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शुद्ध लाभ 11.5% बढ़ा

नई दिल्ली। रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जीसीपीएल) का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 11.5 प्रतिशत बढ़कर 504.52 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 452.45 करोड़ रुपए था। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 18.31 प्रतिशत बढ़कर 4,225.47 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 3,571.32 करोड़ रुपए थी। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप (जीआईजी) की एफएमसीजी इकाई ने बयान में कहा, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान एकीकृत बिक्री में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बढ़ोतरी का कारण बिक्री की मात्रा में नौ प्रतिशत की वृद्धि है।

बीमा क्लेम में देरी पर कंपनियों को देना होगा अतिरिक्त ब्याज

नई दिल्ली। बीमा दावों के निपटारे में होने वाली देरी पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने दावा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और ग्राहक हितैषी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत यदि कोई बीमा कंपनी तय समय सीमा में क्लेम का भुगतान नहीं करती है, तो उसे बैंक दर से दो प्रतिशत अधिक ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना होगा। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर बीमा दावों के निस्तारण की लगातार निगरानी कर रही है। इसके लिए बीमा भरोसा पोर्टल समेत अन्य माध्यमों से ग्राहकों की शिकायतों और क्लेम से जुड़े मामलों पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने दावा खारिज करने की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी बनाया है।

जेम ने रचा इतिहास, 20 लाख करोड़ रुपए का कारोबार पार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के ऑनलाइन पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने देश के डिजिटल गवर्नेंस सफर में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। आगामी 9 अगस्त को यह प्लेटफॉर्म अपनी सेवा के 10 वर्ष पूरे करने जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 7 अगस्त 2026 तक इस पोर्टल के जरिए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संचयी खरीद पूरी की जा चुकी है, जिसके लिए कुल 3.7 करोड़ से अधिक ऑर्डर दिए गए। जेम की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीक-आधारित, पारदर्शी और कुशल बनाना था। शुरुआती दौर (वित्त वर्ष 2016-17) में इस प्लेटफॉर्म का वार्षिक कारोबार (जेम) मात्र 422 करोड़ रुपए था, जो आज इस विशाल स्तर पर पहुंच गया है।

मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजने से किसानों को मिला मुनाफा

नई दिल्ली। बिहार के जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त 'मिथिला मखाना' ने वैश्विक बाजार में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बिहार से पहली बार 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना समुद्री मार्ग के जरिए ऑस्ट्रेलिया निर्यात किया गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से भेजी गई यह खेप सीधे दरभंगा के स्थानीय किसानों से खरीदी गई है, जिससे उन्हें स्थानीय बाजार की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक मुनाफा मिला है। कनाडा भेजे गए इस मूल्य-वर्धित मखाने से स्थानीय किसानों को पहले की तुलना में 50 प्रतिशत से भी अधिक दाम मिले थे।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता का स्वर्णिम अध्याय का आगाज

विनोद सिंह तकियावाला

ऊर्जा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और सामाजिक समृद्धि की आधारशिला होती है।इक्कीसवीं सदी में ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ केवल बिजली उत्पादन या पेट्रोलियम संसाधनों तक सीमित नहीं रह गया है,बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, घरेलू विनिर्माण,ऊर्जा भंडारण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ गया है।भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस गति से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है,उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश केवल ऊर्जा उपभोक्ता नहीं,बल्कि वैश्विक हरित ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है।

नई दिल्ली में आयोजित ऊर्जा सम्मेलन में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा साझा किए गए आँकड़े इस परिवर्तन की सशक्त तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब तक 50 लाख परिवारों को लाभ मिल चुका है। यह उपलब्धि केवल एक सरकारी योजना की सफलता नहीं,बल्कि भारत के ऊर्जा इतिहास में जनभागीदारी पर आधारित एक नई क्रांति का संकेत है। सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अक्टूबर 2025 तक जहाँ देश में प्रतिदिन लगभग 5,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा रहे थे, वहीं जुलाई 2026 तक यह संख्या बढ़कर 16,000 से अधिक प्रतिदिन पहुँच गई। अर्थात् मात्र कुछ महीनों में स्थापना की गति तीन गुना से अधिक हो गई।यह आँकड़ा बताता है कि स्वच्छ ऊर्जा अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रही,बल्कि करोड़ों भारतीय परिवारों का जनआंदोलन बन चुकी है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य केवल बिजली बिल कम करना नहीं है। यह योजना प्रत्येक परिवार को ऊर्जा उत्पादक बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल है। घरों की छतों पर स्थापित सौर संयंत्र दिन के समय बिजली उत्पन्न करते हैं। आवश्यकता से अधिक बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है,जिससे उपभोक्ता आर्थिक लाभ भी अर्जित कर सकते हैं।इससे बिजली वितरण कंपनियों पर दबाव कम होता है तथा देश में विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। भारत आज लगभग 300 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता के ऐतिहासिक पड़ाव के निकट पहुँच चुका है। सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता विकसित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य केवल जलवायु परिवर्तन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति भर नहीं है, बल्कि ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का भी आधार है।स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत की सफलता के पीछे अनेक दूरदर्शी नीतिगत निर्णय हैं। सरकार ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लागू की है, जिससे घरेलू विनिर्माण को नई गति मिली है। इसके अतिरिक्त ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कार्यक्रम के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की क्षमता बढ़ाई जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और घटकों पर कर राहत, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए लिथियम-आयन सेल निर्माण हेतु पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट तथा Renewable Energy Equipment Import Monitoring System जैसी पहलों ने उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की है।

आज भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो सौर ऊर्जा विनिर्माण को रणनीतिक क्षेत्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य केवल सौर पैनल आयात करना नहीं, बल्कि उन्हें देश में ही निर्मित कर वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बनाना है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकेगा। स्वच्छ ऊर्जा का लाभ केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा दक्ष उद्योगों तथा आधुनिक परिवहन व्यवस्था को भी नई दिशा प्रदान करती है।

खनिज शक्ति से विकसित होता छत्तीसगढ़

धरती की संपदा से समृद्धि की नई उड़ान

छत्तीसगढ़ बना खनिज, उद्योग और रोजगार का मजबूत केंद्र

खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ आज देश के अग्रणी खनन राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। बीते वर्षों में राज्य ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी नवाचार को केंद्र में रखकर व्यापक बदलाव किए हैं। वैज्ञानिक खनन, डिजिटल प्रशासन और सतत विकास की सोच ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया है। राज्य में लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, बाक्साइट, टिन अयस्क और अन्य बहुमूल्य खनिजों की प्रचुर उपलब्धता है। हाल के वर्षों में क्रिटिकल, स्ट्रैटेजिक और रेयर अर्थ मिनरल्स की खोजों ने छत्तीसगढ़ को वैश्विक खनिज मानचित्र पर और अधिक मजबूत बनाया है। यही कारण है कि देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। खनन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। राज्य के राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है और खनिज आधारित उद्योगों के विस्तार से रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। राज्य सरकार की नीतियों ने खनिज प्रशासन को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाया है, जिससे निवेशकों का विश्वास भी मजबूत हुआ है।

नई सोच और नई दिशा का छत्तीसगढ़ मॉडल

खनिज संपदा केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि राज्य के सर्वांगीण विकास का मजबूत आधार बन चुकी है। छत्तीसगढ़ ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सतत विकास के समन्वय से एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है। राज्य की यह प्रगति केवल राजस्व वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनहित, रोजगार, आधारभूत विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के खनन और औद्योगिक विकास का सबसे प्रभावशाली केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर दिखाई दे रहा है।

-विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

खनिजों से समृद्ध, संभावनाओं से भरपूर

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध छत्तीसगढ़ आज विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, सोना, तांबा और हीरे जैसे खनिजों के साथ अब लिथियम, निकल और अन्य दुर्लभ खनिजों की संभावनाएं भी तेजी से सामने आई हैं। खनिज संपदा के बेहतर उपयोग और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के कारण राज्य को लगातार बड़ी आर्थिक मजबूती मिली है। अनेक नए खनिज ब्लॉकों की नीलामी और अन्वेषण प्रक्रिया से उद्योगों के लिए नए अवसर तैयार हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा खनिज क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौते भी किए गए हैं। वैज्ञानिक और जिम्मेदार खनन की दिशा में उठाए गए कदमों ने छत्तीसगढ़ को देश के सबसे सक्रिय खनन राज्यों में शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सतत विकास और आधुनिक खनन नीति के जरिए नई उपलब्धियों की ओर बढ़ रहा है।

छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज

कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट, टिन अयस्क, हीरा, सोना, क्वार्टजाइट, मैंगनीज, तांबा, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, क्रोमियम फ्लोराइट, एन्डालूसाइट, बैराइट्स, कोरंडम आदि ।

डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता और गति

खनन क्षेत्र में सुधारों के साथ छत्तीसगढ़ ने डिजिटल प्रशासन को भी नई दिशा दी है। राज्य सरकार ने खनिज प्रशासन को पूर्णतः ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक पोर्टलों और डिजिटल निगरानी व्यवस्था को लागू किया है। इससे अनुमति, निगरानी, वित्तीय स्वीकृति और प्रबंधन की प्रक्रियाएं अधिक सरल और जवाबदेह बनी हैं। जिला खनिज संस्थान न्यास के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिली है। गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत सुविधाओं के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। रेत खदानों के आबंटन से लेकर खनिज प्रबंधन तक की प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर मानव हस्तक्षेप को कम किया गया है।

क्रिटिकल मिनरल्स से भविष्य की तैयारी

छत्तीसगढ़ ने क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के क्षेत्र में भी तेजी से कदम बढ़ाए हैं। राज्य में ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, क्रोमियम, प्लेटिनम समूह के तत्व और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज ने औद्योगिक विकास के नए द्वार खोले हैं। राज्य सरकार ने इन खनिजों के अन्वेषण और विकास को प्राथमिकता देते हुए विशेष सेल का गठन किया है, जो शोध संस्थानों और विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ मिलकर वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा दे रहा है। इससे ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों को भविष्य में नई मजबूती मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है जिसने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में तेजी से पहल की है।

लिथियम ब्लॉक की नीलामी में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने लिथियम ब्लॉक की सफलतापूर्वक ई-नीलामी की है। कोरबा जिले के कटघोरा में मिले लिथियम भंडार (लगभग 250 हेक्टेयर) की नीलामी खान मंत्रालय द्वारा की गई। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस क्षेत्र में लिथियम की पुष्टि की थी। कटघोरा के अलावा बस्तर और सुकमा जिलों में भी लिथियम के अन्वेषण/सर्वेक्षण का काम जारी है।

छत्तीसगढ़ में ई-ऑक्शन प्रणाली

छत्तीसगढ़ में ई-ऑक्शन प्रणाली का उपयोग सरकारी खरीद, खनिज संपदा, और वनोपज (जैसे लकड़ी) की पारदर्शी बिक्री के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना, राजस्व बढ़ाना और प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाना है। रेत खदानों और अन्य प्रमुख खनिजों के खनन पट्टों का आवंटन भी पारदर्शी ई-ऑक्शन प्रणाली के जरिए होता है।

संवाद-48628/1

कोयला ऊर्जा की धड़कन

कोरबा, सरगुजा, कोरिया और रायगढ़ जिले कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। कोरबा को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां से निकलने वाला कोयला देश के बिजली उत्पादन का महत्वपूर्ण आधार है। ऊर्जा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है और राज्य देश की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में अहम योगदान दे रहा है।

लौह अयस्क : उद्योग की रीढ़

दंतेवाड़ा जिले की बैलाडिला खदान एशिया की प्रमुख लौह अयस्क खदानों में गिनी जाती है। यहां से निकला उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क देश के बड़े इस्पात संयंत्रों के साथ विदेशों तक पहुंचता है। लौह अयस्क की प्रचुरता ने छत्तीसगढ़ को इस्पात उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना दिया है। राज्य में स्थापित इस्पात उद्योगों ने आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर तैयार किए हैं।

चूना पत्थर : निर्माण का आधार

बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और जांजगीर-चांपा जैसे जिलों में चूना पत्थर की प्रचुरता ने छत्तीसगढ़ को सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र बना दिया है। वहीं डोलोमाइट का उपयोग इस्पात उद्योग में बड़े स्तर पर किया जाता है। खनिज आधारित उद्योगों के विस्तार से राज्य में निवेश और रोजगार दोनों को मजबूती मिली है। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र औद्योगिक विकास का और बड़ा आधार बनने जा रहा है।

टिन और हीरा : अलग पहचान

देश में टिन उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ की अलग पहचान है। बस्तर क्षेत्र की खदानें इस धातु का प्रमुख स्रोत हैं। देश में जितना भी टिन का उत्पादन होता है वह संपूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ से ही आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मिश्रधातु उद्योगों में टिन का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे इस क्षेत्र की संभावनाएं और मजबूत हुई हैं। राज्य को टिन उत्पादन के मामले में एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।

विकास की बदलती तस्वीर

रोजगार के अवसर
खनन और उससे जुडे उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए रोग के नए अवसर पैदा हुए है।

इनफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
सड़क, रेल, बिजली, जल संसाधन और संचार सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है।

स्थानीय समुदाय को लाभ
शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य सुविधाओं के लिए खनिज निधि का उपयोग बढ़ा है।

उद्योगों का बढ़ता निवेश
बेहतर नीतियाँ और संसाधनों की उपलब्धता से राज्य में निवेश आकर्षित हो रहा है।

जिम्मेदार खनन की दिशा में बड़ी पहल

खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्टार रेटिंग प्रणाली लागू की गई है। कई खदानों को उत्कृष्ट प्रबंधन और वैज्ञानिक खनन के लिए उच्च श्रेणी की रेटिंग प्रदान की गई है। यह राज्य की जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल खनन नीति का प्रमाण है।

प्राथमिकताएं

- सतत और वैज्ञानिक खनन
- पर्यावरण संरक्षण और हरित पहल
- स्थानीय समुदायों का पुनर्वास और विकास
- पारदर्शिता और जिम्मेदार खनन प्रबंधन

चुनौतियाँ और संतुलन की जरूरत

खनन गतिविधियों आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। लेकिन पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा और विस्थापन जैसे मुद्दों पर सतत ध्यान देना जरूरी है।

आगे की राह: खनिज संपदा ने छत्तीसगढ़ को औद्योगिक मानचित्र पर मजबूत स्थान दिलाया है। नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन और सतत दृष्टिकोण के साथ राज्य 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा में अग्रसर है।

धरती की ताकत, लोगों का विश्वास, विकास की नई कहानी

खनिज संपदा छत्तीसगढ़ की पहचान है और यही इसकी प्रगति का आधार भी संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग, उद्योगों के विस्तार और जनहित के संतुलन के साथ राज्य समृद्धि की नई ऊंचाईयों को छूने के लिए तैयार है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.